रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त, 29 1970/भाद्र 7, 1892

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 1970/BHADRA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं ।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 14th August 1970

S.O. 2817.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the Government of West Bengal, hereby nominates Shri B. S. Raghavan, Secretary, Department of Co-operation, Government of West Bengal, as the Chief Electoral Officer for the State of West Bengal, with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri S. K. Mukerjee.

[No. 154/14/70.]

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2817.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से श्री एस० के० मुकर्जी के स्थान पर पश्चिमी बंगाल सरकार के सहकारिता विभाग के सचिव

श्री वी० एस० राघवन को, उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक, पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है ।

[सं० 154/1/70]

ORDERS

New Delhi, the 30th July 1970

S.O. 2818.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dalip Chand, S/o Shri Bakshi, Village and Post Office Ladhwara Tahsil and District Kangra, Himachal Pradesh, a contesting candidate for election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from 41-Nurpur Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dalip Chand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No HP-LA/41/67.]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2818 —यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 41नूरपुर सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दलीप चन्द सुपुत्र श्री बख्शी, ग्राम व पो० आ० लदवाड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दलीप चन्द को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

[सं० हि० प्र०-वि० स० 4/67]

New Delhi, the 4th August 1970

S.O. 2819.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri B. Tiwari, R/O 27-L/4, Station Road, P.O. Burma Mines, Jamshedpur, District Singhbhum (Bihar), a contesting candidate for the mid-term election to the Bihar Legislative

Assembly held in 1969 from 288-Seraikella Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri B. Tiwari to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/288/69(102).]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2819.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के लिए फरवरी 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए सराय के ला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बी० तिवारी, निवासी 27 एल०/4, स्टेशन रोड, पो० बर्मा माइन्स, जमशेदपुर, जिला सिंहभूम (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बी० तिवारी को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/288/69 (102)]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव, ।

ORDERS

New Delhi, the 29th July 1970

S.O. 2820.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kishore Chatterjee, Village Shyamsundarpur, P.O Ukhra, District Burdwan (West Bengal) a contesting candidate for the mid-term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from 252-Faridpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kishore Chatterjee to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/252/69/(40).]

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2820.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 252-फरीदपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री किशोर चटर्जी, ग्राम श्यामसुन्दर, पो० उखरा, जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री किशोर चटर्जी को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य के विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० प० ब०-वि० सं० 252/69(40)]

S.O. 2821.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anjani Kumar Misra, S/o Shri Uma Datta Misra, R/o Village Mahadevan Tola, Fatehpur, District Fatehpur, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 291-Bindki Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2 And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anjani Kumar Misra, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/291/69(72).]

एस० ओ० 2821.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 291 बिन्दकी सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अंजनीकुमार मिश्र सुपुत्र श्री उमा दत्त मिश्र, निवासी गाव महादेवन टोला, फतेहपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अंजनी कुमार मिश्र को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं० 291/69(72)]

S.O. 2822.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hira Lal, S/o Shri Murlidhar, R/o 432, Jalesar Road, Firozabad, District Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 354-Jalesar (SC) Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder.

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hira Lal, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/69(73).]

एस० ओ० 2822—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए 354—निर्वाचन के लिये जलेसर (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हीरालाल, सुपुत्र श्री मुरलीधर, निवासी 432 जलेसर रोड, फिरोजाबाद, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हीरालाल को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० उ० प्र०—वि० स०/354/69(73)]

S.O. 2823.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Laxman Prasad, S/o Shri Tula, R/o Village Dhakia Khurd, Post Office Neemgaon, District Kheri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for mid-term election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 70-Bankeyganj Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Laxman Prasad, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP-LA/70/69(74).]

एस० ओ० 2823.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 70—बांकेगंज सभा निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लक्ष्मण प्रसाद सुपुत्र श्री तुला निवासी गांव ढखिया खुर्द, डा० नीमगांव, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लक्ष्मण प्रसाद को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/70/69 (74).]

S.O. 2824.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Walli Ullah Siddiqi, R/o Village Satimabad, P.O Bodhia Kala, District Kheri, Uttar Pradesh a contesting candidate for mid-term election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 72-Nighasan Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Walli Ullah Siddiqi, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP-LA/72/69(75).]

एस० ओ० 2824.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 72—निघासन सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वलीउल्ला सिद्दीकी, निवासी, गांव सलीमाबाद, डा० बोधिया, जिला खीरी उत्तर प्रदेश ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वलीउल्ला सिद्दीकी को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं/72/69(57).]

S.O. 2825.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Buddha S/o Shri Cheda, R/o Village Magrena P.O. Mohamdi, District Kheri Uttar Pradesh a contesting candidate for mid-term general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 67-Mohamdi Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Buddha, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period or three years from the date of this order.

[No. UP-LA/67/69(76).]

एस० ओ० 2825.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 67-मोहमदी सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बुद्धा सुपुत्र श्री चेदा, निवासी गांव मगरेना, डा० मोहमदी जिला खीरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बुद्धा को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स० 67/69 (76)]

S.O. 2826.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tirbhuwan Nath S/o Shri Kandhai, R/o Village Rampur Maya P.O. Mayabhikhi, District Faizabad, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 135-Maya Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder.

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tirbhuwan S/o Shri Kandhai, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/135/69(77).]

एस० ओ० 2826.— यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 135–माया सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री त्रिभुवन नाथ सुपुत्र श्री कन्धाई, निवासी गांव रामपुरमया, डा० भीखी, जिला फजाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोश लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टकरण नहीं दिया हैं ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है :

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10–क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री त्रिभुवन नाथ सुपुत्र श्री कन्धाई को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की

विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/135/69(77)]

S.O. 2827.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dashrath Lal Tripathi S/o, Shri Ram Narain, Village Sora, Post Office Ganga Ganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 110-Sataon Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dashrath Lal Tripathi, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/110/69(78)]

एस०ओ० 2827.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 110-सतांव सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दशरथ लाल त्रिपाठी सुपुत्र श्री राम नारायन, निवासी गांव सोरा डा० गंगा गज, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दशरथ लाल त्रिपाठी को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स० 110/69(78)]

S.O. 2828.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mihi Lal S/o Shri Hardeen, R/o Village Panditpur, P.O Sohwal, District Faizabad, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 139-Sohwal Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made threundr;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mihi Lal S/o Shri Hardeen, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/139/69(79.)]

एस० ओ० 2828.—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया ह कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 139 सोहावल सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री मिहीलाल सुपुत्र श्री हरदीन, निवासी गाव पितपुर डा० सोहावाल जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ,

और यत., उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया ह , तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ;

अत , अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मिहीलाल सुपुत्र श्री हरदीन को संसद के दोनो सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि, के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[म० उ० प्र०–वि० स० 139/69(79)]

S.O. 2829.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwan Din, S/o Shri Kali, R/o Village Jamurawan Post Office Garehri, District Rae Bareli contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 107-Bachhrawan Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

2 And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure,

3 Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwan Din, S/o Shri Kali, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. UP-LA/107/69(80).]

एस० ओ० 2829—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 107-बछरावा सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री भगवान दीन सुपुत्र श्री काली निवासी गाव जमुरावा, डा० गडेहरी, जिला राय बरेली उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ,

और, यत., उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भगवानदीन सुपुत्र श्री काली को ससद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ?

[सं० उ० प्र०–वि० स० 107/69 (80)]

S.O. 2830.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gauri *alias* Gauri Shanker, S/o Shri Antoo, R/o 65/254 Lahartara, District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 246-Varanasi Cantonment Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gauri *alias* Gauri Shanker, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/246/69 (81).]

एस० ओ० 2830.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 246वाराणसी कैंटूनमैंट सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गौरी उर्फ श्री गौरी शंकर सुपुत्र श्री अंटू निवासी 65/254, लहरतारा, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गौरी उर्फ गौरी शंकर को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/246/69 (81).]

S.O. 2831.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raghubir Prasad, S/o Shri Gokul Chand, R/o Mohalla Guru Nanak Nagar, Rae Bareli, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 246-Varanasi Cantonment Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raghubir Prasad, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/246/69 (82).]

एस० ओ० 2831.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 246 वाराणसी कैंटूनमेंट सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रघुवीर प्रसाद, सुपुत्र श्री गोकुल चन्द, निवासी मोहल्ला गुरुनानक नगर, राय बरेली, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रघुवीर प्रसाद को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि०-स० 246/69(82)]

S.O. 2832.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagarnath Prasad *alias* Netaji, S/o Shri Raghunandan, R/o village and Post Office, Phulwaria, District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 246-Varanasi Cantonment Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagarnath Prasad *alias* Netaji, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/246/69 (83).]

एस० ओ० 2832.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 246-वाराणसी कैंटूनमेंट सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगरनाथ प्रसाद उर्फ नेताजी सुपुत्र रघुनन्दन, निवासी गाव तथा डा० फुलवरिया, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगरनाथ प्रसाद उर्फ नेता जी को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स० 246/69(83)]

S.O. 2833.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheo Adhar S/o Shri Durjan, R/o Village and Post Office, Duhali, Tehsil Ghatampur, District Kanpur, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 290-Khajuha Assembly Constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheo Adhar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/290/69(84).]

एस० ओ० 2833— यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 290—अजुहा सभा निर्वाचन – क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवाधार सुपुत्र श्री दुर्जन, निवासी गाव तथा डा० दहेली, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है ? तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ।

अत:, अब, उक्त धिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवाधार को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य का विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तरीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०–वि० स०/290/69(84)]

New Delhi the 30th July 1970

S.O. 2834.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Sudhar, S/o Shri Jhimmal, R/o Village Bharthara, Post Office Lohata, District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for mid-term general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 249-Araziline Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure:

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Sudhar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/249/69 (85).]

नई दिल्ली, 30 जुलाई 1970

एस० ओ० 2834.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए मध्यावधि साधारण निर्वाचन के लिए 249-आराजी लाइन सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सुधार सुपुत्र श्री झिम्मल निवासी गांव भरथरा, डा० लोहता जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों को लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान भी हो गया है कि उसके पास उस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री रामसुधार को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा

विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/249/69(85)]

S.O. 2835.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anadi Kumar Bera, Village & P.O Shibkalinagar, District 24-Parganas (West Bengal), a contesting candidate for the mid-term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from 116-Kakdwip Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anadi Kumar Bera to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. WB-LA/116/69(41).]

एस० ओ० 2835.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 69 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 116 काक द्वीप निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनादि कुमार बेरा, ग्राम एवं० पो० शिवकालिगर, जिला 24 परगना, (पश्चिमी बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि इसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनादि कुमार बेरा को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० प० ब०-वि० स०/116/69(41)]

S.O. 2836.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shitala *alias* Shitala Singh, S/o Shri Deo Nandan, R/o Village Tadiya, Jakhini, District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for mid-term general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 249-Araziline Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shitala *alias* Shitala Singh, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/249/69(86).]

एस० ओ० 2836.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 249आगरा लाइन सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शीतला उर्फ शीतला सिंह सुपुत्र श्री देव नन्दन निवासी गांव टडिया, जखिनी, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान भी हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शीतला उर्फ शीतला सिंह को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/249/69(86)]

New Delhi, the 1st August 1970

S.O. 2837.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiv Narain S/o Shri Panna Lal, R/o Village and P.O. Jayamon District Agra, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 359-Dayalbagh Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Narain, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No UP-LA/359/69(87).]

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2837.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 359- दयालबाग सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवनारायण सुपुत्र श्री पन्नालाल, निवासी गांव व डा० श्यामों, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवनारायण को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/359/69 (87)]

G.S.R. 2839.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 2 of S/o Shri Mawasi Ram, Garhi Bhadoriya Post Office Lohamandi, Agra, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 359-Dayalbagh Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Ganesh, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP-LA/359/69(88).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 2838.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 359 दयालबाग सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव गनेश सुपुत्र श्री मवासी राम, गढ़ी भदौरिया, डा० लोहमण्डी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव गनेश को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/359/69 (88)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th August 1970

S.O. 2839.—In pursuance of clause (c) of sub-secton (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby declares the Canadian Citizenship Act (as embodied in the 1968 Office Consolidation of the Canadian Citizenship Act) to be an enactment making provision for the citizenship of Canada.

[No. 24/75/69-I.C.]

J. C. AGARWAL, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1970

एस० ओ० 2839.—नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 उपधारा (1) के खण्ड (ग) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कनेडियन सिटिजनशिप एक्ट (जैसा कि वह कनेडियन सिटिजनशिप एक्ट के 1968 के आफिस कंसालडेशन में सन्निविष्ट है) को कनाडा की नागरिकता के लिए उपबन्ध करने वाली अधिनियमति घोषित करती है ।

[सं० 24/75/69—आई० सी०]

ज० च० अग्रवाल, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 10th July 1970

S.O. 2840.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 3rd July, 1970

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	30,56,73,000
		Rupee Coin	2,89,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,77,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	..
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	10,14,09,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances Held Abroad*	102,00,14,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	Investments**	92,52,19,000
		Loans and Advances to: —	
		(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	52,67,75,000
Deposits—		Loans and Advances to : —	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	290,57,95,000
(a) Government—		(ii) State Co-operative Banks††	218,92,63,000
		(iii) Others	2,47,01,000
(i) Central Government	65,54,81,000		

LIABILITIES		ASSETS	
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund—	
(ii) State Governments	7,89,78,000	(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	34,32,25,000
		(ii) State Co-operative Bank	20,22,50,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(b)) Banks—		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02 000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund—	
(i) Scheduled Commercial Banks	180,88,85,000		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	8,98,53,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	4,23,96,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	79,02,000		
(iv) Other Banks	25,03,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund—	
c) Others	165,25,03,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	25,26,71,000
Bill's payable	39,00,99,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
Other Liabilities	29,57,50,000	Other Assets	62,60 95,000
Rupees	957,19,54,000	Rupees	957,19,54,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary over-drafts to State Governments.

†Includes Rs 170,27,80,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 8th day of July 1970.

An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ending the 3rd day of July, 1970.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	30,56,73,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in Circulation	40,48,44,57,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
			(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		4079,01,30,000	Foreign Securities	386,42,00,000	
			TOTAL		568,95,11,000
			Rupee Coin		52 51,61,000
			Government of India Rupee Securities		3457,54,58,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
TOTAL LIABILITIES		4079,01,30,000	TOTAL ASSETS		4079,01,30,000

The 8th day of July, 1970.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F. 3(3)-BC/70.]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2840.—3 जुलाई, 1970 को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	30,56,73,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,89,000
		छोटा सिक्का	4,77,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	..
		(ख) विदेशी	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल	10,14,09,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	102,00,14,000
		निवेश**	92,52,19,000
जमा राशियां :—		ऋण और अग्रिम :—	
(क) सरकारी			
(i) केन्द्रीय सरकार	65,54,81,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	7,89,78,000	(ii) राज्य सरकारों को@	52,67,75,000
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	290,57,95,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	180,88,85,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	218,92,63,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,98,53,000	(iii) दूसरों को	2,47,01,000

(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	79,02,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से	
(iv) अन्य बैंक . . .	25,03,000	ऋण, अग्रिम और निवेश :—	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
(ग) अन्य . . .	165,25,03,000	(i) राज्य सरकारों को . . .	34,32,25,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	20,22,50,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . .	. .
देय बिल . .	39,00,99,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	9,57,02,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम :—	
अन्य देयताएं	29,57,50,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम .	4,23,96,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	26,26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	. .
		अन्य आस्तियां	62,60,95,000
रुपये	957,19,54,000	रुपये	957,19,54,000

*नकदी, मांगदेय जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 170,27,80,000रु० शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 8 जुलाई, 1970

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 3 जुलाई, 1970 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट . .	30,56,73,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— (क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट	4048,44,57,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ . .	..	
जारी किए गए कुल नोट		4079,01,30,000	विदेशी प्रतिभूतियां	386,42,00,000	
			जोड़ . .		568,95,11,000
			रुपये का सिक्का		52,51,61,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		3457,54,58,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र .		..
कुल देयताएं . .		4079,01,30,000	कुल आस्तियां .		4079,01,30,000

तारीख : 8 जुलाई 1970

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर ।

[सं० एफ० 3(3)-बी० सी०/70]

New Delhi, the 17th July 1970

S. O. 2841.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 10th July, 1970.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	19,89,87,000
		Rupee Coin	3,24,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	5,23,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000		
		(*a*) Internal	..
		(*b*) External	..
		(*c*) Government Treasury Bills	8,17,26,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances held Abroad*	100,35,08,000
		Investments**	116,38,21,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations Fund)	95,00,00,000		
		(*i*) Central Government	..
		(*ii*) State Governments@	64,80,70,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(*a*) Government		(*i*) Scheduled Commercial Banks†	254,13,95,000
(*i*) Central Government	57,86,69,000	(*ii*) State Co-operative Banks††	210,48,49,000

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
(ii) State Governments	6,28,77,000	(iii) Others	2,06,01,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund—	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	179,39,10,000	(i) State Governments	34,32,23,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	8,42,59,000	(ii) State Co-operative Banks	20,09,78,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	76,92,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	22,54,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	9,57,02,000
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	4,07,71,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund:—	
(c) Others	160,98,69,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	26,26,71,000
Bills Payable	25,73,20,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Other Liabilities	28,90,29,000	Other Assets	56,87,30,000
Rupees.	927,58,79,000	Rupees.	927,58,79,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 144,37,80,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 15th day of July, 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 10th day of July, 1970.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	19,89,87,000		Gold Coin and Bullion :—		
			(a) Held in India	182,53,11,000	
Notes in circulation	4059,18,93,000		(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		4079,08,80,000	Foreign Securities	386,42,00,000	
			TOTAL		568,95,1 000
			Rupee Coin		52,59,14,000
			Government of India Rupee Securities		3457,54,55,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
TOTAL LIABILITIES		4079,08,80,000	TOTAL ASSETS		4079,08,80,000

Dated the 15th day of July, 1970.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F. 3 (3)-BC/70.]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2841.—10 जुलाई 1970 को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण।

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	19,89,87,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,24,000
		छोटा सिक्का	5,23,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	..
		(ख) विदेशी	..
		(ग) सरकारी ख़जाना बिल	8,17,26,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	100,35,08,000
		निवेश *	116,38,21,000
जमा राशियां :—			
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	57,86,69,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	6,28,77,000	(ii) राज्य सरकारों को@	64,80,70,000
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	254,13,95,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	179,39,10,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	210,48,49,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,42,59,000	(iii) दूसरों को	2,06,01,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	

		(क) ऋण और अग्रिम:—	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	76,92,000	(i) राज्य सरकारों को	34,32,23,000
(iv) अन्य बैंक	22,54,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,09,78,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
(ग) अन्य	160,98,69,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,57,02,000
देय बिल	25,73,20,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	4,07,71,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	
अन्य देयताएं	28,90,29,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	26,26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	56,87,30,000
रुपये	927,58,79,000	रुपये	927,58,79,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 144,37,80,000 रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 15 जुलाई, 1970।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जुलाई 1970 की 10 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट . .	19,89,87,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	4059,18,93,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	386,42,00,000	
जारी किए गए कुल नोट		4079,08,80,000	जोड़ .		568,95,11,000
			रुपये का सिक्का		52,59,14,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		3457,54,55,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		
कुल देयताएं . .		4079,08,80,000	कुल आस्तियां		4079,08,80,000

तारीख : 15 जुलाई, 1970

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर ।

[सं० फ० 3(3)—बी० सी०/70]

New Delhi, the 24th July 1970

S.O. 2842.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 17th July, 1970

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	23,17,83,000
		Rupee Coin	2,71,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	5,15,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(*a*) Internal	..
		(*b*) External	..
		(*c*) Government Treasury Bills	14,89,28,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances Held Abroad*	103,25,62,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	Investments**	161,07,07,000
		Loans and Advances to :—	
		(*i*) Central Government	..
		(*ii*) State Governments @	74,47,85,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
		(*i*) Scheduled Commercial Banks†	286,63,75,000
		(*ii*) State Co-operative Banks††	211,90,55,000
(a) Government :—		(*iii*) Others	1,87,51,000
(*i*) Central Government	60,56,89,000		

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund :—	
(*ii*) State Governments	8,11,37,000	(*a*) Loans and Advances to :—	
		(*i*) State Governments	34,32,25,000
		(*ii*) State Co-operative Banks	21,27,17,000
(*b*) Banks		(*iii*) Central Land Mortgage Banks . . .	..
		(*b*) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund :—	
(*i*) Scheduled Commercial Banks . .	184,80,46,000		
(*ii*) Scheduled State Co-operative Banks	8,62,03,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks . .	4,05,16,000
(*iii*) Non-Scheduled State Co-operative Banks	71,62,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial	
(*iv*) Other Banks	20,39,000	Credit (Long Term Operations) Fund:—	
		(*a*) Loans and Advances to the Development Bank	26,26,71,000
(*c*) Others	235,50,52,000	(*b*) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Bills Payable	31,94,37,000	Other Assets	47,67,86,000
Other Liabilities	31,05,84,000		
Rupees .	1020,53,49,000	Rupees .	1020,53,49,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 160,04,80,000 advanced to Scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 22nd day of July, 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 17th day of July, 1970

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	23,17 83,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation . .	4008,36,92,000		(*a*) Held in India	182,53,11,000	
			(*b*) Held outside India . . .	..	
Total Notes issued . . .		4031,54,75,000	Foreign Securities	386,42,00,000	
			TOTAL		568,95,11,000
			Rupee Coin . .		55,04 92,000
			Government of India Rupee Securities		3407,54,72,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper . . .		..
TOTAL LIABILITIES . . .		4031,54,75,000	TOTAL ASSETS		4031,54,75,000

Dated the 22nd day of July, 1970.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F. 3(3)-BC/70.]

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1970

ऐस० ओ० 2842.—17 जुलाई 1970 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी . . .	5,00,00,000	नोट . .	23,17,83,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का . .	2,71,000
		छोटा सिक्का .	5,15,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		खरीदे और भुनाये गये बिल:—	
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि . . .	172,00,00,000		
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	..
(स्थिरीकरण) निधि . . .	37,00,00,000	(ख) विदेशी . . .	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल . .	14,89,28,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		विदेशों में रखा हुआ बकाया* . .	103,25,62,000
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि . . .	95,00,00,000	निवेश** . .	161,07,07,000
जमा राशियां :—		ऋण और अग्रिम :—	
(क) सरकारी		(i) केन्द्रीय सरकार को . . .	..
(i) केन्द्रीय सरकार . . .	60,56,89,000	(ii) राज्य सरकारों को . . .	74,47,85,000
(ii) राज्य सरकारें . . .	8,11,37,000		
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकोंको . .	286,63,75,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . .	184,80,46,000	(i) राज्य सहकारी बैंकों को . .	211,90,55,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . .	8,62,03,000	(ii) दूसरों को . . .	1,87,51,000

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :–	
		(क) ऋण और अग्रिम :–	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	71,62,000	(i) राज्य सरकारों को . . .	34,32,25,000
(iv) अन्य बैंक . . .	20,39,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	21,27,17,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . .	. .
(ग) अन्य	235,50,52,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,57,02,000
देय बिल	31,94,37,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम .	4,05,16,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :–	
अन्य देयताएं	31,05,84,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम .	26,26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश	. .
		अन्य आस्तियां . . .	47,67,86,000
रुपये	1020,53,49,000	रुपये	1020,53,49,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं ।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।

*रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 160,04,80,000/- रुपये शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

तारीख : 22 जुलाई, 1970 ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जुलाई, 1970 की 17 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	23,17,83,000		सोन का सिक्का और बुलियन:—		
संचालन में नोट	4008,36,92,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	386,42,00,000	
जारी किए गए कुल नोट		4031,54,75,000			
			जोड़		568,95,11,000
			रुपये का सिक्का		55,04,92,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		3407,54,72,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं		4031,54,75,000	कुल आस्तियां		4031,54,75,000

तारीख 22 जुलाई, 1970।

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर ।

[सं० फ० 3 (3)—बी० सी०/70]

New Delhi, the 31st July 1970

S.O. 2843.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 24th July, 1970.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	19,93,73,000
		Rupee Coin	3,24,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	5,35,000
		Bills Purchased and Discounted:- -	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	(a) Internal	..
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	13,76,07,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balance Held Abroad*	94,58,80,000
		Investments**	190,47,50,000
		Loans and Advances to:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments @	52,26,88,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	127,81,40,000
Deposits:—		(ii) State Co-operative Banks††	217,52,38,000
(a) Government—		(iii) Others	1,89,01,00
(i) Central Government	61,52,61,000		
(ii) State Governments	10,95,39,000		

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks—		(a) Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks . . .	193,07,63,000	(i) State Governments	34,32,25,000
		(ii) State Co-operative Banks	22,28,69,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks . .	8,99,83,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks .	76,62,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02,000
(iv) Other Banks	18,94,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks . .	4,01,45,000
(c) Others	160,82,10,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund . . .	
Bills Payable	30,99,83,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank .	26,26,71,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Other Liabilities	30,28,96,000	Other Assets	41,76,43,000
Rupees .	956,61,91,000	Rupees . .	956,61,91,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 111,27,20,000/- advanced to scheduled commercial banks against unsance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural (Credit Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 29th day of July, 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 24th day of July, 1970.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	19,93,73,000		Gold Coin and Bullion:—		
			(a) Held in India	182,53,11,000	
			(b) Held outside India	..	
Notes in circulation	3934,39,38,000				
Total Notes issued		3954,93,11,000	Foreign Securities	386,42,00,000	
			TOTAL		568,95,11,000
			Rupee Coin		58,42,99,000
			Government of India Rupee Securities		3327,55,01,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
TOTAL LIABILITIES		3954,93,11,000	TOTAL ASSETS		3954,93,11,000

Dated the 29th day of July, 1970.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F.3(3)-BC/70].

K. YESURATNAM, Under Secy

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2843.—24 जुलाई, 1970 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	19,93,73,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,24,000
		छोटा सिक्का	5,35,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	..
		(ख) विदेशी	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल	13,76,07,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	94,68,80,000
		निवेश**	190,47,50,000
जमा राशियां :—		ऋण और अग्रिम :	
(क) सरकारी			
(i) केन्द्रीय सरकार	61,52,61,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	10,95,39,000	(ii) राज्य सरकारों को@	52,26,88,000
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	227,81,40,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	193,07,63,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	217,52,38,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,99,83,000	(iii) दूसरों को	1,89,01,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	

		(क) ऋण और अग्रिम :—	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	76,62,000	(i) राज्य सरकारों को . . .	34,32,25,000
(iv) अन्य बैंक . . .	18,94,000	(ii) राज्य सहकारी बैंको को . .	22,23,69,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको को .	..
(ग) अन्य	160,82,10,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको के डिबेचरो मे निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,57,02,000
देय बिल	30,99,83,000	राज्य सहकारी बैंको को ऋण और अग्रिम . .	4,01 45 000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	
अन्य देयताएं	30,28,96,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम .	26.26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाडो/डिबचरो मे निवेश अन्य आस्तिया . . .	41,76,43,000
रुपये	956,61,91,000	रुपये	956,61,91,000

* नकदी आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतिया शामिल है।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए) निधि मे से किये गये निवेश शामिल नही है।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही है, परन्तु राज्य सरकारो के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल है।

†रिजर्व बैंक आफ इडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको को मीयादी बिलो पर अग्रिम दिये गये 111.27,20,000 रुपये शामिल है।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही है।

तारीख : 29 जुलाई, 1970।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जुलाई, 1970 की 24 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट . .	19,93,73,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— (क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
परिचलन में नोट .	3934,99,38,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ . .	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां .	386,42,00,000	
जारी किए गए कुल नोट .		3954,93,11,000	जोड़ . .		568,95,11,000
			रुपये का सिक्का .		58,42,99,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . .		3327,55,01,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र .		..
कुल देयताएं . .		3954,93,11,000	कुल आस्तियां .		3954,93,11,000

तारीख : 29 जुलाई, 1970।

एस० जगन्नाथन्,
गवर्नर।

[सं० एफ० 3 (3)—बी० सी०/70]

के० यसुरत्नम, अनुसचिव।

New Delhi, the 6th August 1970

S.O. 2844.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur, till the 1st August 1971, in respect of the immovable property held by it at Thoppumpady, Palluruthy, Cochin, Ernakulam District, Kerala State.

[No. F. 15(17)-BC/70.]

K. YESURATNAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त 1970

एस० ओ० 2844.—बैंकिंग विनियम अधिनियमन 1949 (1949 के 10 वें) की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड त्रिचर पर केरल राज्य के तोप्पुमपडी पल्लुरुति कोचीन जिला एरनाकुलम स्थित उसकी अचल सम्पत्ति के संबंध में पहली अगस्त 1971 तक लागू नहीं होंगे ।

[सं० एफ० 15 (17) बी० सी०/70]

के० येसुरत्नम,

अनुसचिव, भारत सरकार।

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th July 1970

S.O. 2845.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Savings Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, published with the Notification of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 1670 dated the 14th June, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Savings Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, for item (iii) of the Foot Note, the following item shall be substituted, namely:—

"(iii) No person

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. F. 16(25)-NS/70.]

P. N. MALAVIYA, Under Secy.

अर्थ विभाग

नई दिल्ली, 30 जुलाई 1970

एस० ओ० 2825.—कानूनीनियमऔर आदेश—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) की 14 जून, 1960 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1670 में प्रकाशित राष्ट्रीय बचत संगठन (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियमावली 1960 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात्

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय बचत संगठन (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जायगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तारीख से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचत संगठन (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियमावली, 1960 में, पाद-टिप्पणी की मद (III) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायगी, अर्थात्

"(III) ऐसा व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसी स्त्री/ऐसे पुरुष से विवाह कर लिया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया हो, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्त किए जाने के लिये पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति को तथा उससे विवाह करने वाले अन्य व्यक्ति को, उन पर लागू होने वाली व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत ऐसा विवाह करने की अनुमति है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

[संख्या एफ० 16(25)एन०एस०/70]

पी० एन० मालवीय, अनुसचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX ESTABLISHMENT

New Delhi, 31st January, 1970

S.O. 2846.—In pursuance of clause (b) of sub rule (ii) of rule 2 of the Appellate Tribunal Rule 1946, the Central Government was pleased to appoint Shri P. Srinivasan, Inspecting Assistan Commissioner of Income-tax, Rang -II, Ahmedabad as Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal, Ahmedabad from the afternoon of the 29th November, 1969 to the forenoon of the 5th January, 1970. Shri E.D. Helms, Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Allahabad as Authorised Representative, Allahabad from the afternoon of the 14th August 1969 to the afternoon of the 2nd January, 1970 and Shri Ganga Prasad, Income-tax Officer Class II, Deoghar (then Bihar and Orissa charge) as Junior Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal, Patna from 25th May, 1966 to 3rd November, 1969, to appear, plead and act for any Income-tax authority who is a party to any proceedings before the Income-tax Appellate Tribunal.

No. 33.—Consequent on their transfers, the powers conferred on the following officers by the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification noted against each are hereby withdrawn with effect from the date shown against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Notification No. and date	Date from which powers are withdrawn
1	2	3	4
1	Sh. D. G. Pradhan, Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal Allahabad.	No. 218-I.T. Establishments dt. 26-5-66	14-8-69(AN)
2	Sh. V. Satyanarayana Rao, Junior Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal, Hyderabad.	No. 50-I.T. Establishments dt. 23-2-67	1-7-69(FN)
3	Sh. P. P. Kaistha, Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi.	No. 323-I.T. Establishments dt. 22-8-69	3-11-69(FN)
4	Sh. K. N. Anantharama Ayyar, Authorised Representative. Income-tax Appellate Tribunal, Kochin.	No. 63-I.T. Establishments dt. 6-2-69	1-12-69(AN)

No. 34.—In pursuance of clause (b) of sub rule (ii) of rule 2 of the Appellate Tribunal Rules, 1946, the Central Government has been pleased to appoint the undermentioned officers as Authorised Representative/Junior Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal with effect from the date noted against them to appear, plead and act for any Income-tax authority who is a party to any proceedings before the Income-tax Appellate Tribunal:—

Sl. No.	Name of the Officer	Appointed as	Date of appointment
1	Sh. M. S. Shakir, Income Tax Officer, Class II, Andhra Pradesh charge.	Junior authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal. Hyderabad.	1-9-69(AN)
2	Sh. S. N. Singh, Income Tax Officer, Class II, Bihar charge.	Junior Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal, Patna.	3-11-69(FN)
3	Sh. Kanwal Krishan, Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Bombay.	Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi.	24-11-69(FN)
4	Sh. D. S. Thapar, Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, Belgaum.	Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal, Chandigarh.	17-11-69(FN)
5	Sh. S. K. Roy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Dibrugarh.	Authorised Representative, Income-tax Appellate Tribunal. Allahabad.	2-1-70(AN)
6	Sh. R. S. Aulakh, Income Tax Officer, Class II, Punjab charge.	Junior Authorised Representative Income-tax Appellate Tribunal, Chandigarh.	1-1-70(FN)

[Nos. 32—34/F. No. 57/20/69-Ad. VI]

M. G. THOMAS,
Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

आयकर स्थापन

नई दिल्ली, 31 जनवरी 1970

एस० ओ० 2846.—सं० 32 अपील अधिकरण नियम 1946 के नियम 2 के उपनियम (ii) के खण्ड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री पी० पी० श्रीनिवासन, सहायक आयकर

श्रायुक्त (निरीक्षण) रेंज II अहमदाबाद को प्राधिकृत प्रतिनिधि श्रायकर अपील अधिकरण अहमदाबाद के रूप में 29 नवम्बर 1969 के अपराह्न से 5 जनवरी 1970 के पूर्वाह्न तक श्री ई० डी० हेल्मा सहायक श्रायकर श्रायुक्त (अपील) इलाहाबाद को प्राधिकृत प्रतिनिधि इलाहाबाद के रूप में 14 अगस्त 1969 के अपराह्न से 2 जनवरी 1970 के अपराह्न तक और श्री गंगा प्रसाद श्रायकर अधिकारी श्रेणी II देवघर(तत्स- मय बिहार और उड़ीसा भारसाधन) को कनिष्ठ प्राधिकृत प्रतिनिधि श्रायकर अपील अधिकरण पटना के रूप में 25 मई 1966 से 3 नवम्बर 1969 तक किसी श्रायकर प्राधिकारी की ओर से जो श्रायकर अपील अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में पक्षकार हैं हाजिर होने अभिवचन करने तथा कार्य करने के लिए नियुक्त करती है।

सं० 33–वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक नामने लिखित अधिसूचनाओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों, उनके स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से एतद्द्वारा प्रत्याहृत की जाती है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	अधिसूचना की संख्या और तारीख	वह तारीख जिससे शक्तियां प्रत्याहृत की गई हैं
1	2	3	4
1	श्री डी० जी० प्रधान, प्राधिकृत प्रतिनिधि	संख्या 218–श्रायकर स्थापन तारीख 26–5–66	14–8–69 (अप०)
2	श्री वी० सत्यनारायणराव, कनिष्ठ प्राधिकृत प्रतिनिधि, श्रायकर अपील अधिकरण, हैदराबाद।	सं० 50 श्रायकर स्थापन तारीख 23–2–67	1–7–69 (पूर्वा०)
3	श्री पी० पी० कायस्थ, प्राधिकृत प्रतिनिधि, श्रायकर अपील अधिकरण दिल्ली।	सं० 323–श्रायकर स्थापन तारीख 22–8–69	3–11–69 (पूर्वा०)
4	श्री के० एन० अनंथारामा अय्यर, प्राधिकृत, प्रतिनिधि, श्रायकर अपील अधिकरण, कोचीन।	सं० 63–श्रायकर स्थापन तारीख 6–2–69	1–12–69 ([illegible])

सं० 34–अपील अधिकरण नियम, 1946, के नियम 2 के उपनियम (II) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को श्रायकर अपील अधिकरण के प्राधिकृत तिनिधि/कनिष्ठ प्राधिकृत के रूप में, किसी श्रायकर प्राधिकारी की ओर से जो श्रायकर अपील अधिकरण

के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में प्रक्षकार हैं, उनके सामने लिखी तारीख से हाजिर होने, अभिवचन करने तथा कार्य करने के लिए नियुक्त करती है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	के रूप में नियुक्त	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
1	श्री एम० एस० शाकिर, आयकर अधिकारी, वर्ग 2, आंध्र प्रदेश भारसाधन	कनिष्ठ प्राधिकृत प्रतिनिधि आयकर अपील अधिकरण हैदराबाद	1–9–69 (अप०)
2	श्री एस० एन० सिंह, आयकर अधिकारी, वर्ग 2, बिहार भारसाधक	कनिष्ठ प्राधिकृत प्रतिनिधि, आयकर अपील अधिकरण पटना	3–11–69 (पूर्वा०)
3	श्री कंवल कृष्ण, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) मुम्बई	प्राधिकृत, प्रतिनिधि, आयकर अपील अधिकरण, पटना	24–11–69 (पूर्वा०)
4	श्री डी० एस० थापर, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) बेलगाम	प्राधिकृत प्रतिनिधि, आयकर अपील अधिकरण, चण्डीगढ़	17–11–69 (पूर्वा०)
5	श्री एस० के० राय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) डिब्रुगढ़	प्राधिकृत प्रतिनिधि, आयकर अपील अधिकरण, इलाहाबाद	2–1–70 (अप०)
6	श्री आर० एस० औलख, आयकर अधिकारी, वर्ग 2, पंजाब भारसाधन	कनिष्ठ प्राधिकृत प्रतिनिधि आयकर अपील अधिकरण, चण्डीगढ़।	1–1–70 (पूर्वा०)

[सं 32–34/एफ० सं० 57/20/69–एडी० VI]

एम० जी० थामस,

अवर सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 29th August 1970

S.O. 2847.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 1-Customs dated the 1st January, 1970, namely:—

In the first paragraph of the said notification, in clause (c) of the proviso, for the words "imported within four months", the words "shipped by sea within one month, or despatched by air within a fortnight," shall be substituted.

[No. 82/F. No. 90/79/70-L.C.I.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1970

का० आ० 2847 :—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 1—सीमा शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1970, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में परन्तु क के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"(ग) माल सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति के पहुंचने के एक मास के भीतर पोत द्वारा या एक पखवाड़े के भीतर विमान द्वारा या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क कलक्टर किसी मामले विशेष में अनुज्ञात करे, भेजा गया है ।"

[सं० 82/एफ सं० 90/79/70—एल सी]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 29th Auguts 1970

S.O. 2848.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 21/F. 22/4/66-Cus. IV, dated the 11th March, 1967, namely:—

In the Table below the said notification, for the existing entry under column 2, the entry "Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone" shall be substituted.

[No. 81/F. No. 22/13/70-Cus. IV.]

J. DATTA, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2848 :—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 21/एफ० 22/4/66—सीमा शुल्क 4, तारीख 11 मार्च, 1967 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, स्तम्भ 2 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार जोन" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[सं० 81/एफ सं० 22/13/70—सी० शु० 4]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव, ।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDERS

New Delhi, the 11th August 1970

S.O. 2849.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Board of Direct Taxes hereby empowers every person appointed to be an Additional Commissioner of Income-tax and Additional Commissioner of Income-tax (Recovery) under sub-section (1) of section 117 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) and specified in column (3) of the Table annexed hereto to exercise the functions of a Commissioner of Gift-tax under the first mentioned Act, who shall have concurrent jurisdiction in respect of any areas or persons or classes of persons along with the Commissioners of Gift-tax as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, and the Central Board of Direct Taxes hereby specifies that they shall also perform the functions of a Commissioner of Gift-tax as specified in the Annexure to this order in relation to the said areas or persons or classes of persons.

TABLE

Sl. No.	Commissioners of Gift-tax	Additional Commissioners of Income-tax and Additional Commissioners of Income-tax (Recovery)
1	2	3
1	Commissioner of Gift-tax, Andhra Pradesh-I, Hyderabad-34.	Additional Commissioner of Income-tax Andhra Pradesh-I, Hyderabad-34.
2	Commissioner of Gift-tax, Andhra Pradesh-II, Hyderabad-34.	Additional Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh-II, Hyderabad-34.
3	Commissioner of Gift-tax, Assam, Nagaland, Manipur and Tripura, Shillong-I.	Additional Commissioner of Income-tax, Assam, Nagaland, Manipur and Tripura, Shillong-I.
4	Commissioner of Gift-tax, Bihar, Patna.	Additional Commissioner of Income-tax, Bihar, Patna.
5	Commissioner of Gift-tax, Bombay City I, Bombay.	Additional Commissioner of Income-tax, Bombay City-I, Bombay.
6	Commissioner of Gift-tax, Bombay City-II, Bombay.	Additional Commissioner of Income-tax, Bombay City-II, Bombay.
7	Commissioner of Gift-tax, Bombay City-III, Bombay.	Additional Commissioner of Income-tax, Bombay City-III, Bombay.
8	Commissioner of Gift-tax, Delhi-I, New Delhi.	Additional Commissioner of Income-tax, Delhi-I, New Delhi.
9	Commissioner of Gift-tax, Delhi-II, New Delhi.	Additional Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi.
10	Commissioner of Gift-tax, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi-III, New Delhi.	Additional Commissioner of Income-tax, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi-III, New Delhi.
11	Commissioner of Gift-tax, Gujarat, Ahmedabad.	Additional Commissioner of Income-tax, Gujarat-I, Ahmedabad.
12	Commissioner of Gift-tax, Gujarat-II, Ahmedabad.	Additional Commissioner of Income-tax, Gujarat-II, Ahmedabad.
13	Commissioner of Gift-tax, Gujarat-III, Ahmedabad.	Additional Commissioner of Income-tax, Gujarat-III, Ahmedabad.
14	Commissioner of Gift-tax, Kerala, Ernakulam (South), Cochin-16.	Additional Commissioner of Income-tax, Kerala, Ernakulam (South), Cochin-16.
15	Commissioner of Gift-tax, Madhya Pradesh, Bhopal.	Additional Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh, Bhopal.
16	Commissioner of Gift-tax, Vidarbha & Marathwada, Nagpur.	Additional Commissioner of Income-tax, Vidarbha & Marathwada, Nagpur.
17	Commissioner of Gift-tax, Madras-I, Madras-34.	Additional Commissioner of Income-tax, Madras-I, Madras-34.
18	Commissioner of Gift-tax, Madras-II, Madras-34.	Additional Commissioner of Income-tax, Madras-II, Madras-34.
19	Commissioner of Gift-tax, Bangalore-1.	Additional Commissioner of Income-tax, Bangalore-I.

1	2	3
20	Commissioner of Gift-tax, Orissa, Bhubaneshwar-I.	Additional Commissioner of Income-tax, Orissa, Bhubaneshwar-I.
21	Commissioner of Gift-tax, Poona.	Additional Commissioner of Income-tax, Poona.
22	Commissioner of Gift-tax, Punjab, Jammu & Kashmir & Chandigarh, Patiala.	Additional Commissioner of Income-tax Punjab, Jammu & Kashmir & Chandigarh, Patiala.
23	Commissioner of Gift-tax, Rajasthan, Jaipur.	Additional Commissioner of Income-tax, Rajasthan, Jaipur.
24	Commissioner of Gift-tax, Lucknow.	Additional Commissioner of Income-tax, Lucknow.
25	Commissioner of Gift-tax, Kanpur.	Additional Commissioner of Income-tax, Kanpur.
26	Commissioner of Gift-tax, West Bengal-I, Calcutta-I.	Additional Commissioner of Income-tax, West Bengal-I, Calcutta-I.
27	Commissioner of Gift-tax, West Bengal-II, Calcutta-I.	Additional Commissioner of Income-tax, West Bengal-II, Calcutta-I.
28	Commissioner of Gift-tax, West Bengal-III, Calcutta-I.	Additional Commissioner of Income-tax, West Bengal-III, Calcutta-I.
29	Commissioner of Gift-tax, West Bengal-I Commissioner of Gift-tax, West Bengal-II Commissioner of Gift-tax, West Bengal-III Commissioner of Gift-tax, (Central) Calcutta.	Additional Commissioner of Income-tax, (Recovery), Calcutta.
30	Commissioner of Gift-tax, Bombay City-I Commissioner of Gift-tax, Bombay City-II Commissioner of Gift-tax, Bombay City-III Commissioner of Gift-tax (Central) Bombay.	Additional Commissioner of Income-tax, (Recovery), Bombay.
31	Commissioner of Gift-tax, Madras-I Commissioner of Gift-tax, Madras-II Commissioner of Gift-tax (Central) Madras.	Additiohal Commissioner of Income-tax, (Recovery) Madras.
32	Commissioner of Gift-tax, Delhi-I Commissioner of Gift-tax, Delhi-II Commissioner of Gift-tax, Delhi-III Commissioner of Gift-tax, (Central) Delhi	Additional Commissioner of Income-tax, (Recovery) Delhi.

ANNEXURE

1. Revisionary powers under sub-section (1) and (2) of Section 24.
2. Sanction for proceedings and issue of notice under clause (I) of sub-section (1) of section 16.
3. Determination of appearance by authorised representatives under Section 42.
4. All the functions of a Commissioner of Gift-tax under the Gift-tax Act, 1958 in connection with the recovery of taxes including stay of demands and withholding of refunds under sub-section (2) of section 33A.

[No. 13/315/2/70-WT-

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2849 :—दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त आयकर आयुक्त और अतिरिक्त आयकर आयक्त (वसूली) के रूप में नियुक्त, और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में

विनिर्दिष्ट, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके पास उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दानकर आयुक्तों के साथ-साथ किन्हीं क्षेत्रों या व्यक्तियों या व्यक्ति के वर्गों की बाबत समवर्ती अधिकारिता होगी, प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन दानकर आयुक्त के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करता है, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि वे उक्त क्षेत्रों या व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में इस आदेश के उपबन्धों में यथा विनिर्दिष्ट दानकर आयुक्तों के कृत्यों का भी पालन करेंगे ।

सारणी

क्रम सं०	आयुक्त	अतिरिक्त आयकर आयुक्त और अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली)
1	2	3
1.	दानकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश–I, हैदराबाद-34 ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश–I हैदराबाद–34 ।
2.	दानकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश–II हैदराबाद-34.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश–II, हैदराबाद–34 ।
3.	दानकर आयुक्त, असम, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा, शिलांग–I ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, असम, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा, शिलांग–I
4.	दानकर आयुक्त, बिहार, पटना ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, बिहार, पटना ।
5.	दानकर आयुक्त, मुम्बई नगर–I, मम्बई ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मुम्बई नगर–I, मुम्बई ।
6.	दानकर आयुक्त, मुम्बई नगर–II. मुम्बई ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मुम्बई नगर–II, मुम्बई ।
7.	दानकर आयुक्त, मुम्बई नगर–III. मुम्बई,	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मुम्बई नगर–III, मुम्बई ।
8.	दानकर आयुक्त दिल्ली-I, नई दिल्ली ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, दिल्ली–I, नई दिल्ली ।
9.	दानकर आयुक्त, दिल्ली–II, नई दिल्ली ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, दिल्ली–II नई दिल्ली ।
10.	दानकर आयुक्त, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली–III, नई दिल्ली ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, हरियाणा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली–III, नई दिल्ली ।
11.	दानकर आयुक्त, गुजरात-I, अहमदाबाद ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात–I, अहमदाबाद ।
12.	दानकर आयुक्त, गुजरात–II अहमदाबाद ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात–II अहमदाबाद ।
13.	दानकर आयुक्त, गुजरात–III अहमदाबाद ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात–III अहमदाबाद ।
14.	दानकर आयुक्त, केरल, अर्नाकुलम (दक्षिण) कोचीन–16.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, केरल अर्नाकुलम, (दक्षिण) कोचीन–16.
15.	दानकर आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल ।

1	2	3
16.	दानकर आयुक्त, विदर्भ और मराठवाड़ा, नागपुर।	अतिरिक्त आयकर, आयुक्त, विदर्भ और मराठवाड़ा, नागपुर।
17.	दानकर आयुक्त, मद्रास–I, मद्रास–34।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मद्रास–I, मद्रास–34।
18.	दानकर आयुक्त, मद्रास–II, मद्रास–34।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मद्रास–II, मद्रास–34।
19.	दानकर आयुक्त, मैसूर, बंगलौर–I	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मैसूर, बंगलौर–I
20.	दानकर आयुक्त, उड़ीसा, भुवनेश्वर–I.।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, उड़ीसा, भुवनेश्वर–I
21.	दानकर आयुक्त, पूना।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पूना।
22.	दानकर आयुक्त, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा चण्डीगढ़, पटियाला।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा चण्डीगढ़, पटियाला।
23.	दानकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
24.	दानकर आयुक्त, लखनऊ।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, लखनऊ।
25.	दानकर आयुक्त, कानपुर।	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, कानपुर।
26.	दानकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II, कलकत्ता–1.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त पश्चिमी बंगाल–II, कलकत्ता–1।
27.	दानकर आयुक्त, पश्चिमी बंगला–II, कलकत्ता–1.	अतिरिक्त अयाकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II, कलकत्ता–1
28.	दानकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–III, कलकत्ता-1.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल-III, कलकत्ता–1
29.	दानकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल-I दानकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II दानकर आयुक्त पश्चिमी बंगाल–III दानकर आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली), कलकत्ता।
30.	दानकर आयुक्त, मुम्बई नगर–I दानकर आयुक्त, मुम्बई नगर–II दानकर आयुक्त, मुम्बई, नगर–III दानकर आयुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली), मुम्बई।
31.	दानकर आयुक्त, मद्रास–I दानकर आयुक्त, मद्रास–II दानकर आयुक्त (केन्द्रीय), मद्रास	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली), मद्रास।
32.	दानकर आयुक्त, दिल्ली–I दानकर आयुक्त, दिल्ली–II दानकर आयुक्त, दिल्ली–III दानकर आयुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली). दिल्ली।

उपाबन्ध

1. धारा 24 की उपधारा (1) और (2) के अधीन पुनरीक्षण शक्तियां ।
2. धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कार्रवाई करने और नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी।
3. धारा 43 के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपसंजात होना का अवधारण।
4. करों की वसूली के संबंध में, दानकर अधिनियम, 1958 के अधीन दानकर आयुक्त के सभी कृत्य, जिनमें धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन मांगों की रोक और प्रतिदाय का विधारण सम्मिलित है।

[सं० 13/315/2/70–डब्ल्यू० टी०]

S.O. 2850.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby empowers every person appointed to be an Additional Commissioner of Income-tax and Additional Commissioner of Income-tax (Recovery) under sub-section (1) of section 117 of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) and specified in column (3) of the Table annexed hereto, to exercise the functions of a Commissioner of Wealth-tax under the first-mentioned Act in respect of any individual, Hindu undivided family or company who shall concurrent jurisdiction in respect of any individual Hindu a undivided family or company along with the Commissioners of Wealth-tax specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, and the Central Board of Direct Taxes hereby specifies that they shall also perform the functions of a Commissioner of Wealth-tax as specified in the Annexure to this Order, in relation to the said classes of persons.

TABLE

Sl. No.	Commissioner of Wealth Tax	Additional Commissioner of Income-tax and Additional Commissioner of Income tax (Recovery)
1	2	3
1	Commissioner of Wealth tax, Andhra Pradesh-I, Hyderabad-34.	Additional Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh-I, Hyderabad-34.
2	Commissioner of Wealth tax, Andhra Pradesh-II, Hyderabad-34.	Additional Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh-II, Hyderabad-34.
3	Commissioner of Wealth tax, Assam Nagaland, Manipur and Tripura, Shillong-1.	Additional Commissioner of Income-tax Assam, Nagaland, Manipur and Tripura, Shillong-1.
4	Commissioner of Wealth tax, Bihar, Patna.	Additional Commissioner of Income-tax, Bihar, Patna.
5	Commissioner of Wealth tax, Bombay City I, Bombay.	Additional Commissioner of Incometax, Bombay City I, Bombay.
6	Commissioner of Wealth tax, Bombay City II, Bombay.	Additional Commissioner of Incometax, Bombay City II, Bombay.
7	Commissioner of Wealth tax, Bombay City III, Bombay.	Additional Commissioner of Incometax, Bombay City III, Bombay.
8	Commissioner of Wealth tax, Delhi I, New Delhi.	Additional Commissioner of Incometax, Delhi-I, New Delhi.
9	Commissioner of Wealth Tax, Delhi-II, New Delhi.	Additional Commissioner of Incometax, Delhi-II, New Delhi.
10	Commissioner of Wealth tax, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi-III, New Delhi.	Additional Commissioner of Incometax, Haryana. Himachal Pradesh and Delhi-III, New Delhi.
11	Commissioner of Wealth tax, Gujarat I, Ahmedabad.	Additional Commissioner of Incometax, Gujarat I, Ahmedabad.

1	2	3
12	Commissioner of Wealth tax, Gujarat II, Ahmedabad.	Additional Commissioner of Income-tax, Gujarat-II, Ahmedabad.
13	Commissioner of Wealth tax, Gujarat III, Ahmedabad.	Additional Commissioner of Incometax, Gujarat-III, Ahmedabad.
14	Commissioner of Wealth tax, Kerala, Ernakulam (South) Cochin-16.	Additional Commissioner of Income-tax, Kerala, Ernakulam (South) Cochin-16.
15	Commissioner of Wealth tax, Madhya Pradesh, Bhopal.	Additional Commissioner of Incometax, Madhya Pradesh, Bhopal.
16	Commissioner of Wealth tax, Vidarbha and Marathwada, Nagpur.	Additional Commissioner of Incometax, Vidarbha and Marathwada, Nagpur.
17	Commissioner of Wealth tax, Madras-I, Madras-34.	Additional Commissioner of Incometax, Madras-I, Madras-34.
18	Commissioner of Wealth Tax, Madras-II, Madras-34.	Additional Commissioner of Incometax, Madras-II, Madras-34.
19	Commissioner of Wealth Tax, Mysore, Bangalore-I.	Additional Commissioner of Incometax, Mysore, Bangalore-1.
20	Commissioner of Wealth tax, Orissa, Bhuvaneshwar-1.	Additional Commissioner of Incometax, Orissa, Bhuvaneshwar-1.
21	Commissioner of Wealth tax, Poona.	Additional Commissioner of Incometax, Poona.
22	Commissioner of Wealth tax, Punjab, Jammu & Kashmir & Chandigarh, Patiala.	Additional Commissioner of Incometax, Punjab, Jammu & Kashmir & Chandigarh, Patiala.
23	Commissioner of Wealth tax, Rajasthan, Jaipur.	Additional Commissioner of Incometax, Rajasthan, Jaipur.
24	Commissioner of Wealth tax, Lucknow.	Additional Commissioner of Incometax, Lucknow.
25	Commissioner of Wealth tax, Kanpur.	Additional Commissioner of Incometax, Kanpur.
26	Commissioner of Wealth tax, West Bengal-I, Calcutta-1.	Additional Commissioner of Incometax, West Bengal-I, Calcutta-1.
27	Commissioner of Wealth Tax, West Bengal-II, Calcutta-1.	Additional Commissioner of Incometax, West Bengal-II, Calcutta-1.
28	Commissioner of Wealth tax, West Bengal-III, Calcutta-1.	Additional Commissioner of Incometax West Bengal-III. Calcutta-1.
29	Commissioner of Wealth tax, West Bengal-I, Commissioner of Wealth tax, West Bengal-II, Commissioner of Wealth tax, West Bengal-III, Commissioner of Wealth tax, (Central) Calcutta.	Additional Commissioner of Incometax, (Recovery) Calcutta.
30	Commissioner of Wealth tax, Bombay City-I, Commissioner of Wealth tax, Bombay City-II, Commissioner of Wealth tax, Bombay City-III, Commissioner of Wealth tax, (Central) Bombay.	Additional Commissioner of Incometax (Recovery) Bombay.
31	Commissioner of Wealth tax, Madras-I, Commissioner of Wealth tax, Madras-II, Commissioner of Wealth tax, (Central) Madras.	Additional Commissioner of Incometax (Recovery) Madras.
32	Commissioner of Wealth tax, Delhi-I, Commissioner of Wealth tax Delhi-II, Commissioner of Wealth tax, Delhi-III, Commissioner of Wealth tax, (Central) Delhi	Additional Commissioner of Incometax (Recovery) Delhi.

ANNEXURE A

1. Revisionary powers under sub-section (1) and (2) of Section 25.
2. Sanction for proceedings and issue of notice under clause (a) of sub-section (1) of Section 17.
3. Determination of appearance by authorised representatives under sub-section (1) of Section 44.

ANNEXURE B

All the functions of a Commissioner Wealth, tax, under the Wealth tax Act, 1957 in connection with the recovery of taxes including stay of demands and withholding of refunds under sub-section (2) of Section 34A.

[No. 14/315/2/70-W.]

एस० ओ० 2850.—धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त आयकर आयुक्त और अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली) के रूप में नियुक्त, और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके पास उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट धनकर आयुक्तों के साथ साथ, किसी व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कम्पनी की बाबत समवर्ती अधिकारिता होगी, प्रथम-वर्णित अधिनियम के अधीन किसी व्यष्टि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कम्पनी की बाबत धनकर आयुक्त के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करता है, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि वे व्यक्ति उक्त वर्गों के सम्बन्ध में इस आदेश के उपाबन्धों में यथाविनिर्दिष्ट धनकर आयुक्तों के कृत्यों का भी पालन करेंगे।

सारणी

क्रम संख्या	धनकर आयुक्त	अतिरिक्त आयकर आयुक्त और अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली)
1	2	3
1.	धनकर आयुक्त, आंन्ध्र प्रदेश–I, हैदराबाद-34.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, आंन्ध्र प्रदेश–I, हैदराबाद–34.
2.	धनकर आयुक्त, आंन्ध्र प्रदेश–II, हैदराबाद-34.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, आंन्ध्र प्रदेश–II, हैदराबाद–34.
3.	धनकर आयुक्त, असम, नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा, शिलांग–1.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त असम, नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा, शिलांग –1
4.	धनकर आयुक्त बिहार, पटना.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त बिहार, पटना
5.	धनकर आयुक्त, मुम्बई नगर–I, मुम्बई.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मुम्बई नगर–I, मुम्बई।
6.	धनकर आयुक्त, मुम्बई नगर –II, मुम्बई.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मुम्बई नगर–II, मुम्बई.
7.	धनकर आयुक्त, मुम्बई नगर-III, मुम्बई.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मुम्बई नगर–III, मुम्बई.

1	2	3
8.	धनकर आयुक्त दिल्ली-I, नई दिल्ली.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, दिल्ली-I, नई दिल्ली,
9.	धनकर आयुक्त दिल्ली-II, नई दिल्ली.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, दिल्ली-II नई दिल्ली.
10.	धनकर आयुक्त, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली–III, नई दिल्ली.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली-III, नई दिल्ली.
11.	धनकर आयुक्त, गुजरात–I, अहमदाबाद,	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात-I, अहमदाबाद.
12.	धनकर आयुक्त गुजरात–II, अहमदाबाद.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात-II, अहमदाबाद.
13.	धनकर आयुक्त गुजरात-III, अहमदाबाद.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात-III, अहमदाबाद
14.	धनकर आयुक्त, केरल, अर्नाकुलम (दक्षिण) कोचीन-16.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, केरल, अर्नाकुलम (दक्षिण) कोचीन–16.
15.	धनकर आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल.
16.	धनकर आयुक्त, विदर्भ और मराठवाड़ा, नागपुर.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, विदर्भ और मराट-वाड़ा, नगपुर.
17.	धनकर आयुक्त, मद्रास–I, मद्रास–34.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मद्रास-I, मद्रास–34.
18.	धनकर आयुक्त, मद्रास–II, मद्रास–34.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मद्रास-II, मद्रास–34.
19.	धनकर आयुक्त, मैसूर, बंगलौर–1.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मैसूर, बंगलौर–1.
20.	धनकर आयुक्त, उड़ीसा, भुवनेश्वर–1.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त उड़ीसा, भुवनेश्वर–1.
21.	धनकर आयुक्त, पूना.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पूना.
22.	धनकर आयुक्त पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा चण्डीगढ़, पटियाला.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पंजाब, जम्मू और कशमीर तथा चण्डीगढ़, पटियाला.
23.	धनकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर,
24.	धनकर आयुक्त, लखनऊ.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, लखनऊ.
25.	धनकर आयुक्त, कानपुर.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, कानपुर.
26.	धनकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल II, कलकत्ता–1.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II, कलकत्ता -1.
27.	धनकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल-II, कलकत्ता–1	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II, कलकत्ता-1.
28.	धनकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II, कलकत्ता–1,	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II, कलकत्ता–1.
29.	धनकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–I, धनकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल–II, धनकर आयुक्त पश्चिमी बंगाल–III, धनकर आयुक्त, (केन्द्रीय) कलकत्ता	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली) कलकत्ता.
30	धनकर आयुक्त मुम्बई नगर–I, धनकर आयुक्त, मुम्बई नगर–II धनकर आयुक्त, मुम्बई नगर–III, धनकर आयुक्त, (केन्द्रीय) मुम्बई.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली) मुम्बई.

1	2	3
31.	धनकर आयुक्त मद्रास–I धनकर आयुक्त, मद्रास–II धनकर आयुक्त (केन्द्रीय), मद्रास	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली), मद्रास
32.	धनकर आयुक्त, दिल्ली–I धनकर आयुक्त, दिल्ली–II धनकर आयुक्त, दिल्ली–III धनकर आयुक्त, (केन्द्रीय), दिल्ली	अतिरिक्त आयकर आयुक्त (वसूली), दिल्ली

उपाबन्ध क

1. धारा 25 की उपधारा (1) और (2) के अधीन पुनरीक्षण शक्तियां।

धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कार्रवाई करने और नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपसंजात होने का धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अवधारण।

उपाबन्ध ख

करों की वसूली के सम्बन्ध में, धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन, धनकर आयुक्त सभी कृत्य, जिनमें धारा 34क की उपधारा (2) के अधीन मांगों की रोक और प्रतिदाय का विधारण सम्मिलित है।

[सं० 14/315/2/70-डब्ल्यू० टी०]

बलबीर सिंह, सचिव।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDERS

New Delhi, the 7th August 1970

S.O. 2851.—The National Coal Development Corporation Ltd., Durbhanga House Ranchi (Bihar) were granted an Import licence No. G/CG/2027860/D/PG/30/H/28/CG.II, dated 19th March, 1969, for Rs. 46,35,610/- (Rupees forty six lakh, thirty five thousand six hundred and ten only). They have applied for issue of duplicate copy for Exchange Control Purposes of the said licence on the ground that the original Exchange Control Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the Exchange Control copy was not utilised.

2. In support of this contention, the applicants have filed an affidavit. I am satisfied that the original exchange control copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated the 7th December, 1955 as amended the Exchange Control copy of said Licence No. G/CG/2027360/D/PG/30/H/28/CG.II, dated 19th March, 1969 is hereby cancelled.

3. A duplicate (Exchange Control copy) of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. CG.II/44(6)/68-69.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2851.—दि नेशनल कोल डवेलपमेंट कारपोरेशन लि०, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) को 46,35,610 (छयालिस लाख, पैंतालीस हजार छः सौ दस रुपये मात्र) रुपये के लिए आयात लाइसेंस संख्या जी०/सी० जी०/2027860/डी०/पी०जी०/30/एच०/28/सी०जी०/II, दिनांक 19-3-69 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण कार्य के लिए अनुलिपि प्रति जारी कराने के लिए आवेदन किया है, इसके लिए उन्होंने यह आधार दिया है कि उनकी मूल मुद्रा नियंत्रण प्रति खो गई है, किसी गलत जगह पर रख दी गई है। उन्होंने आगे यह बताया है कि मुद्रा नियंत्रण प्रति का उपयोग नहीं किया गया था।

2. इस तक के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ-पत्र जमा किया है। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा नियंत्रण प्रति खो गई है। इसलिए, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 के अनुसार संशोधित, उपधारा 9 (सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपर्युक्त लाइसेंस संख्या/जी० सी० जी०/2027860/डी०/पी० जी०/30/एच०/28/सी० जी०-2, दिनांक 19-3-1969 को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

3. उपर्युक्त लाइसेंस की एक अनुलिपि (मुद्रा नियंत्रण प्रति) लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सी० जी० 2/44 (6)/68-69]

S.O. 2852.—The Chief Conservator of Forests Central Building, Maharashtra State, Poona-1 was granted an Import Licence No. G/CG/2027580/C/XX/C/H/25/CG.II, dated 29th September, 1967 for Rs. 2,650 (Rupees two thousand six hundred and fifty only). They have applied for the issue of duplicate copies both for Customs and Exchange Control purposes for the said licence on the ground that they have lost the licence without having it utilised/registered at any Custom House.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that both the Customs and Exchange Copies of the original licence have been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import Control 1955 dated 7th December, 1955 as amended, the said original licence No. G/CG/2027580/C/XX/C/H/25/CG.II., dated the 29th September, 1967 is hereby cancelled.

3. A duplicate licence (both copies) of the said licence is being issued separately to the licencee. The Chief Conservator of Forests Central Building Maharashtra State Poona-1.

[CG.II/46(26)/67-68.]

P. C. VERMA,
Dy. Chief Controller of Import & Export

एस० ओ० 2852.—सेन्ट्रल बिल्डिंग महाराष्ट्र राज्य, पूना-1 के मुख्य वनपाल को 2,650 (दो हजार,छः सौ पचास रुपये मात्र) रुपये का आयात लाइसेंस संख्या जी०/सी० जी०/2027580/सी०/एक्स० एक्स०/सी०/एच०/सी० जी०-2, दिनांक 29-9-67 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने सीमा-शुल्क और मुद्रा नियंत्रण कार्य दोनों के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां जारी करने के लिए आवेदन किया है। इसके लिए उन्होंने यह आधार दिया है कि बिना उपयोग किए किसी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराए ही लाइसेंस उनके द्वारा खो गया है।

2. इस तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ-पत्र जमा किया है। मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस की सीमा-शुल्क और मुद्रा नियंत्रण दोनों प्रतियां खो गई हैं। इस लिए, आयात नियंत्रण 1955, दिनांक 7-12-1955 के अनुसार संशोधित, उपधारा 9 (सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर,

उपर्युक्त मूल लाइसेंस संख्या जी०/सी० जी०/2027580/सी०/एक्स० एक्स०/सी०/एच०/25/सी० जी-2, दिनांक 29-9-67 इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सेन्ट्रल बिल्डिंग महाराष्ट्र राज्य, पूना-1 के मुख्य वनपाल को उपर्युक्त लाइसेंस का अनुलिपि लाइसेंस (दोनों प्रतियां) अलग से जारी की जा रहीं हैं।

[संख्या सी० जी०-2/46(26)/67-68]

पी० सी० वर्मा,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

MERCHANT SHIPPING

New Delhi, the 20th August, 1970

S.O. 2853.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Bombay). Rules, 1954, the Central Government hereby reconstitutes the Seamen's Employment Board (Foreign-going), Bombay for a period of two years with effect from the date of publication of this notification, with the following members, namely:—

1. The Director General of Shipping, Bombay. 2. The Deputy Director General of Shipping, Incharge of Seamen's Employment Offices. 3. The Labour Commissioner, Bombay. 4. Director, Seamen's Employment Office, Bombay. 5. The Shipping Master, Bombay. 6. The Principal, Seamen's Welfare Officer, Bombay.	Members representing the Government.
7. Shri N. Latif. 8. Capt. Y. K. Chopra. 9. Capt. D. Houghton. 10. Capt. R. D. Kohli. 11. Shri T. S. Narayan. 12. Capt. J. Bruegmann.	Members representing the Ship-owners.
13. Shri K. K. Khadilkar. 14. Shri Leo Barnes. 15. Shri Mohideen Bawa 16. Shri U. M. Almeida. 17. Shri M. Moidoo. 18. Shri Yakub Serang.	Members representing the Seamen.

2. The Director General of Shipping and the Deputy Director General of Shipping, Incharge of Seamen's Employment Office, Bombay, shall respectively, be the Chairman and the Vice-Chairman of the Board.

3. The Director, Seamen's Employment Office. Bombay, shall act as the Secretary of the Board.

[No. 15-MT(4)/70]
B. ROY, Dy. Secy.

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

व्यापारिक पोतपरिवहन

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2853:—भारतीय व्यापारिक पोतपरिवहन (नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई) नियम, 1954, के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार एतद्द्वारा नाविक रोजगार बोर्ड (विदेश गामी) बम्बई का इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित सदस्यों से पुनर्गठन करती है, अर्थात् :—

1. पोतपरिवहन के महानिदेशक, बम्बई ।	सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
2. पोत परिवहन के उपमहानिदेशक, नाविक रोजगार कार्यालयों के कार्यकारी	
3. श्रम आयुक्त, बम्बई ।	
4. निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई ।	
5. पोतपरिवहन मास्टर, बम्बई ।	
6. मुख्य नाविक-कल्याण अधिकारी, बम्बई ।	
7. श्री एन० लतीफ ।	पोत मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
8. कप्तान वाई० के० चोपड़ा ।	
9. कप्तान डी० ह्यूटन ।	
10. कप्तान आर० डी० कोहली ।	
11. श्री टी० एस० नारायण ।	
12. श्री जे० वुगमन्न ।	
13. श्री के० के० खादिलकर ।	नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
14. श्री लिओ बर्नीस ।	
15. श्री मोहिदीन बावा ।	
16. श्री यू० एम० अलमेदा ।	
17. श्री एम० मोइदू ।	
18. श्री याकूब सरेंग ।	

2. पोतपरिवहन के महानिदेशक तथा पोतपरिवहन के उप महानिदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई, के कार्यकारी इस बोर्ड के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ।

3. निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई, इस बोर्ड के सचिव के रूप में काम करेंगे ।

[सं० 15–एम० टी० (4)/70]

बी० राय, उप सचिव ।

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली 12 जनवरी, 1970

का० आ० 274—जयन्ती शिपिंग कम्पनी (नियंत्रण बोर्ड) नियम, 1966 के नियम, 3 के साथ पठित जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्धग्रहण) अधिनियम, 1966 (1966 का 24) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० एन० भण्डारी को श्री एम० एस० भटनागर, जिन्होंने पदत्याग दिया है, के स्थान पर 12 दिसम्बर, 1969 से जयन्ती शिपिंग कम्पनी के नियंत्रण बोर्ड के एक अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और उड्डयन मंत्रालय, परिवहन, जहाजरानी और पर्यटन विभाग (परिवहन स्कंध), की अधिसूचना सं० का० आ० 1781 तारीख 10 जून, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(i) उक्त अधिसूचना में पैरा 1 में क्रम सं० 5 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"5. श्री पी० एन० भण्डारी, सेवा निवृत्त उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक";

(ii) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. श्री पी० एन० भण्डारी, नियंत्रण बोर्ड के एक अंशकालिक सदस्य होंगे।"

[सं० 32–एम डी(II)/69]

बी० पी० श्रीवास्तव, उपसचिव ।

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

ORDER

New Delhi, the 18th August 1970

S.O. 2854.—In the course of a series of discussion held by the Deputy Director of Mines Safety (Electrical Headquarters) with the officials of the National Coal Development Corporation Ltd., at Dhanbad, Ranchi and Banki on the application for relaxation of certain provisions of the Indian Electricity Rules 1956 requested by M/s. National Coal Development Corporation Ltd. in their letter No. CEME/Banki/69/3047-50 dated 13/14th May, 1969 from the Deputy Chief Engineer (E&M) to the Secretary of the Ministry in regard to the proposed supply of energy to Banki and Surakachar at 3300 volts 3 phase delta connected system and underground distribution at 550 volts, 3 phase with unearthed neutral, in line with the practice of power supply arrangement followed and in use for mines in USSR, the system of power supply to Banki and Surakachar mines having been designed and planned according to the practice in USSR, it has been observed that there has been provision of sensing leakage current to each in 3.3 kv supply system and that in the event of any deterioration of insulation resistance below the predetermined value (in the case 50 Kilo-ohms) anywhere in 3.3 kv system, the capacitive currents flowing through the earth return, operate insulation sensing (Monitoring) device which trips the main controlling circuit breaker of the underground system located at the surface sub-station. It has also been seen that when the tripping of the main controlling circuit breaker at the surface sub-station takes place there is (a) an audible signal and (b) a visible signal and flag indication, all these devices being incorporated in the circuit breaker itself. At the same time the circuit breaker in the underground sub-station feeding the faulty feeder gives an indication of existence of fault by glow of neon lamp. It has also been observed that when tripping takes place on account of earth fault it is not possible to switch on the circuit breaker controlling faulty circuit till the fault is removed. In other words, there is a blocking out of the circuit breaker controlling the faulty feeder disallowing reclosing of the same unless the earth fault is cleared and normal healthy condition of the circuit is restored. Therefore, it is considered that 3300 volts delta connected system of supply may not lead to danger provided adequate measures are taken to keep the protective devices incorporated in the system, in perfect working conditions.

550 volts supply system underground with unearthed neutral was also found to have been adequately protected against earth fault by incorporating special earth leakage protective relay.

2. In exercise of the powers conferred by sub-rule 2 of rule 133 of the Indian Electricity Rules, 1956, the Central Government, therefore, hereby directs that (i) the provisions of rule 130 of the said rules requiring earthing of the neutral or mid point of an alternating current system exceeding 30 volts, shall be relaxed in respect of transmission, distribution and use of electrical energy at 3 phase 3300 volts and 550 volts, 3.3 kv supply being of delta connected system and 550 volts underground distribution supply having unearthed neutral, (ii) The provisions of sub-rule (c) of rule 118 shall be relaxed in respect of use of 115 volts 3 phase lighting supply underground without neutral point of 115 volts system being connected with earth and (iii) The provisions of sub-rule (e) of rule 118 shall be relaxed permitting remote control circuit for under ground switch gear being used at 36 volts in place of 30 volts, subject to the following conditions:

(1) To ensure that protective devices provided in the 3300 volts circuit breakers are in perfect working condition they shall be tested at regular intervals but under no circumstances less than once in a fortnight. Such testing shall be recorded in a separate bound-paged register kept for the purpose.

The responsibility of proper observance of testing and maintenance of records shall rest with the management.

The management shall take adequate steps to ensure that the protective devices with special reference to fault current relay, whose efficiency for proper working is checked periodically for its soundness by a competent person not below the rank of Electrical Supervisor/Electrical Foreman.

(2) Earth leagage protective device associated with special earth leakage relays in medium pressure circuit breakers shall be tested for their efficacy atleast once in every 24 hours. If the said protective device is out of order in any circuit

breaker, the supply by the circuit breaker with defective relay shall be kept disconnected until the defective relay is put in working order.

(3) Switch Board attendants, operators and electricians shall be thoroughly trained and duly authorised for handling the circuit breakers and other apparatus with competency and due care to avoid danger.

Provided that the relaxation considered may be amended or withdrawn if considered necessary in the interest of safety.

[No. EL.II.6(6)/69.]

M. RAMANATHAN, Dy. Director (Power).

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2854.—मैं० नेशनल कोल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा उप मुख्य अभियंता (ई० एण्ड एम०) के माध्यम से इस मंत्रालय के सचिव को भेजे गए उन के पत्र संख्या सी० ई० एम० ई०/बांकी/69/3047–50, दिनांक 13/14 मई, 1969 में, बांकी और सूराकाचर खानों में विद्युत की सप्लाई प्रणाली में, जिस का अभिकल्पन और आयोजन रूसी पद्धति के अनुसार किया गया है, रूस में प्रचलित और प्रयुक्त विद्युत की सप्लाई व्यवस्था से सम्बन्धित पद्धति के अनुसार 3300 वोल्ट पर 3 पेजों वाली डेल्टा सम्बद्ध प्रणाली और 500 वोल्ट पर अभूयोजित मध्यग तार के साथ 3 पेजों वाली भूमिगत वितरण प्रणाली द्वारा बांकी और सूराकाचर को ऊर्जा की प्रस्तावित सप्लाई के सम्बन्ध में प्राधिकृत भारतीय बिजली नियमावली, 1956 के कुछ उपबन्धों के शिथिलीकरण के लिये अभ्यावेदन पर धनबाद, रांची और बांकी में नेशनल कोल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि० के अधिकारियों के साथ हुए उपनिदेशक, खान सुरक्षा, (विद्युत मुख्यालय) के वार्ताक्रम के दौरान यह देखने में आया है कि 3.3 के० वी० वाली सप्लाई प्रणाली में भूमि में विद्युत धारा के स्राव को मालूम करने की व्यवस्था है और यदि 3.3 के० वी० प्रणाली में किसी स्थल पर विद्युत रोधन व्यवस्था में प्रतिरोधी शक्ति किसी गड़बड़ी से पूर्व-निर्धारित अंक (इस प्रणाली में 50 किलो ओहूम) से कम हो जाती है तो भूयोजक तार में प्रवाहित हो रही संधारित विद्युत धाराओं (कैपेसिटिव करेंटस) से विद्युत रोधन को मालूम करने वाली (मानीटरिंग) कल चल पड़ती है और वह तल-स्थित उपकेन्द्र की भू-गत प्रणाली की प्रमुख लाइन का नियंत्रण करने वाले सर्किट ब्रेकर को झटका देकर चला देती है। यह भी देखा गया है कि जब भू-तल पर स्थित उप-केन्द्र में मुख्य लाइन का नियंत्रण करने वाला सर्किट ब्रेकर झटके से चल पड़ता है तो (क) श्रव्य संकेत, (ख) दृश्य संकेत मिलते हैं और झंडे का निशान आ जाता है। ये सब कलें सर्किट ब्रेकर मे ही लगी हुई हैं। इसके साथ ही दोषपूर्ण पोषक लाइन को पुष्ट कर रहे भू-गत सर्किट ब्रेकर लेम्प नियोन लैम्प को रोशन करके दोष की विद्यमानता को प्रकट कर देता है। यह भी देखा गया है कि जब भू-योजक तार की खराबी के कारण ट्रिपिंग होता है, उस खराबी को दूर करने वाले सर्किट ब्रेकर को बटन दबा कर उसे चलाना संभव नही है। दूसरे शब्दों में दोषपूर्ण फीडर का नियंत्रण करने वाला सर्किट ब्रेकर अवरुद्ध हो जाता है और उसे दोबारा बन्द नहीं किया जा सकता जब तक कि भू-योजक तार को दोष रहित नही कर दिया जाता और सर्किट की सामान्य स्वास्थ्यपूर्ण स्थिति बहाल नहीं कर दी जाती। अतः यह सोचा गया है कि 3300 वोल्ट वाली डेल्टा सम्बद्ध सप्लाई प्रणाली से कोई खतरा उत्पन्न नही होगा, बशर्ते कि इस प्रणाली में सुरक्षाकारी कलों की व्यवस्था करने और उसे पूर्ण परिचालन स्थिति में रखने के लिये पर्याप्त पग उठाऊ जाएं।

अभूयोजित मध्यग तार वाली 550 वोल्ट की भू-गत सप्लाई प्रणाली भी उसमें भूयोजक तार से बिजली के निःस्राव के प्रति विशेष प्रकार के सुरक्षाकारी रिले की व्यवस्था करने पर, भूयोजन प्रणाली के दोषों के प्रति पर्याप्त-रूपेण सुरक्षित पाई गई है।

2. अतः भारतीय बिजली नियमावली, 1956 के नियम 133 के उपनियम 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि (1) उक्त नियमावली के नियम 130 के उपबन्धों का, जिनके अधीन 30 से अधिक वोल्टों वाली प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली के मध्यग अथवा मध्य पाइंट का भू-योजन जरूरी है, 3 फेज 3300 वोल्ट और 550 वोल्ट पर विद्युतीय उर्जा के पारेषण, वितरण और उपयोग के सम्बन्ध में शिथिलीकरण किया जाता है। 3.3 के० वी० सप्लाई डेल्टा सम्बन्द्ध प्रणाली की होगी और 550 वोल्ट भूगत वितरण सप्लाई का मध्यग अभू-योजित होगा, (2) नियम 118 के उपनियम (ग) के उपबन्धों का शिथिलीकरण 115 वोल्ट 3 फेज, रोशनी के लिए उस भूगत सप्लाई के उपयोग के सम्बन्ध में किया जाता है जिसमें भूयोजक तार के साथ 115 वोल्ट प्रणाली का मध्यग पाइंट संयोजित न हो, और (3) नियम 118 के उपनियम (ङ) के उपबन्धों का शिथिलीकरण किया जाता है और 30 वोल्ट की जगह 36 वोल्ट पर प्रयोग में लाए जा रहे भूगत स्विच गियर के लिए दूरस्थ नियंत्रण सर्किट की अनुमति है ; इस शिथिलीकरण की शर्तें निम्नलिखित होंगी :—

(1) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि 3300 वोल्ट के सर्किट ब्रेकरो मे लगी सुरक्षाकारी कलें पूर्ण परिचालन स्थिति में हों, उनका नियमित समयान्तरालों पर और हर हालत में एक पखवाड़े में कम से कम एक बार परीक्षण किया जाएगा। इन परीक्षणों का रिकार्ण जिल्द चढे एक अलग रजिस्टर मे रखा जायेगा।

ठीक ढग से परीक्षण करने और रिकार्ड के अनुरक्षण की जिम्मेदारी प्रबन्धकर्ताओं की होगी।

प्रबन्धकर्ता इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त पग उठाएगे कि एक सुयोग्य व्यक्ति जिसका पद विद्युत पर्यवेक्षक/विद्युत फोरमैन मे कम न हो, सुरक्षाकारी कलो की, विशेषतः दोषपूर्ण विद्युतधारा को रिले करने वाली कलों की, समय समय पर जांच करे और देखे कि वे दोषरहित हैं और सही परिचालन के लिये दक्ष हैं।

(2) मध्यम दबाव वाले सर्किट ब्रेकरों में विशेष भू-योजक निःस्राव रिले मे सम्बन्धित भू-योजक निःस्राव सुरक्षाकारी कलों की प्रभावकारिता की 24 घंटों में कम से कम एक बार जाच कीजाएगी यदि उक्त सुरक्षाकारी कल किसी सर्किट ब्रेकर में काम करना बन्द कर देती है, तो दोषपूर्ण रिले करने वाले सर्किट ब्रेकर से सप्लाई तब तक के लिये बन्द कर दी जाएगी जब तक कि दोषपूर्ण रिले पुनः ठीक नही हो जाता।

(3) स्विच बोर्ड पर काम करने वालों, चालकों, बिजली मिस्त्रियों को पूर्णतः प्रशिक्षित करके दक्षतापूर्ण ढग से और खतरे मे बचने के लिये पूरी सावधानी के साथ सर्किट ब्रेकरों को चलाने का अधिकार दे दिया जाएगा।

बशर्ते कि सुरक्षा के हित में, यदि आवश्यक समझा गया तो इन शिथिलीकरणों का संशोधन किया जा सकता है और इन्हें वापस लिया जा सकता है।

[सं० ई० एल० टी० 6(6)/69]

एम० रामनाथन,

उपनिदेशक (विद्युत)।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 10th August 1970

S.O. 2855.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum) S.O. No. 1551 dated April, 20, 1970 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention of acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the competent authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For laying Pipeline from Well No. SBA to SOBHASAN-1 (GGS)

State—Gujarat District—Mehsana Taluka—Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	P. Are
HEBUVA . . .	263	0	7	8
	258	0	17	20
	241	0	9	11
	233	0	12	04
	240	0	10	14
	239	0	10	12
	245	0	15	25
	223	0	1	50

[No. 11(1)/70-Lab. & Legis.]

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1970

का० आ० 2855.—यतः पैट्रोलियम, पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 155 तारीख 20-4-1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिओं के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया है।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिओं में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है और उस धारा की उपधरारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी विलंगमों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कुआं संख्या 58ए से सोमासन-1 (जी० जी० एस०) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला महसाना तालुका मेहसाना

गांव	ब्लाक संख्या	हैक्टर	आर	पी आर
हेबुवा	263	0	7	8
	258	0	17	20
	241	0	9	11
	233	0	12	64
	240	0	10	14
	239	0	10	12
	245	0	15	23
	223	0	1	50

[सं० 11/1/70-लेबर एण्ड लेजिस]

S.O. 2856.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum) S.O. No. 1428 dated April 13, 1970 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the competent authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For laying pipeline from drill sites 7, 13, 14, 17 & 18 to GGS at Kosamba

State—Gujarat Districe—Surat Taluka—Mangrol

Village	Survey No.	Hectare	Are	P. Are
For well No. 7 & 14				
KUVERDA	790	0	4	76
	791	0	3	57
	792	0	10	71
	721	0	23	81
	789	0	14	18
For well No. 13				
KUVERDA	211/1	0	7	15
	210	0	5	75
	306/1	0	9	53
	207	0	1	19
	456/1	0	19	53
	473/1	0	4	76
	470	0	4	76
	479	0	11	91
	477	0	2	98
	476	0	2	38
For well No. 17 & 18				
KUVERDA	18	0	9	52
	22/1	0	6	33

[No. 11(3)/69-Lab. & Legis.]

M. V. S. PARASADA RAU,
Under Secy.

का० आ० 2856.—यतः पट्रोलियम, पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1428 तारीख 13-4-70 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया है।

और आगे, यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है और उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी विलंगमों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

व्यधन स्थल 7, 13, 14, 17 तथा 18 से कोसम्बा जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाना

राज्य गुजरात जिला सूरत तालुका मंगलौर

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	आर	पी आर
कुआं संख्या 7 तथा 14 के लिए				
कुवेरडा	790	0	4	76
	791	0	3	57
	792	0	10	71
	721	0	23	81
	789	0	14	18
कुआं संख्या 13 के लिए				
कुवरडा	211/1	0	7	15
	210	0	5	75
	306/1	0	9	53
	207	0	1	19
	456/1	0	19	53
	478/1	0	4	76
	470	0	4	76
	479	0	11	91
	477	0	2	98
	476	0	2	38
कुआ संख्या 17 तथा 18 के लिए				
कुवेरडा	18	0	9	52
	22/1	0	8	33

[सं० 11/3/69-लेबर एण्ड लेजिस]

म० वे० शिव प्रसाद राव, अवर सचिव ।

(Department of Petroleum and Chemicals)

ORDER

New Delhi, the 14th August 1970

S.O. 2857.—In pursuance of paragraphs 22 and 23 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, the Central Government hereby authorises the following officers to exercise the functions and powers specified in the said paragraphs within their respective jurisdiction, namely:—

(i) The Deputy Drugs Controller, West Zone, Bombay.
(ii) The Deputy Drugs Controller, East Zone, Calcutta.
(iii) The Deputy Drugs Controller, North Zone, Ghaziabad.
(iv) The Deputy Drugs Controller, South Zone, Madras.
(v) The Drugs Inspectors, Bombay, Calcutta, Ghaziabad and Madras.

[No. 17(48)/70-CH.III.]

R. J. BHOJWANI, Under Secy.

पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त 1970

एस० ओ०—2857औषधि (कीमत नियन्त्रण) आदेश 1970 के पैराग्राफ्स 22 और 23 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार सीमा में उक्त पैराग्राफ्स में विनिर्दिष्ट कार्यों तथा शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देती है, अर्थात् :—

(i) औषधि उप नियन्त्रक, पश्चिमी क्षेत्र, बम्बई

(ii) औषधि, उप नियन्त्रक, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता

(iii) औषधि उप नियन्त्रक, उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद

(iv) औषधि उप नियन्त्रक, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास

(v) औषधि निरीक्षक बम्बई, कलकत्ता, गाजियाबाद तथा मद्रास

[सं० 17 (48)/70—सी० एच० III]

आर० जे० भोजवानी,

अवर सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

New Delhi, the 11th August 1970

S.O. 2858.—In pursuance of sub-section (3) of section 20, of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Department of Health) No. S.O. 1475, dated the 13th April 1970, namely:—

In the said notification, for the entry "Dean, Medical College, **Aurangabad**", against serial No. 4, the entry "Director, Medical Education and Research, Maharashtra, Bombay", shall be substituted.

[No. F. 4-26/69-MPT.]

R. MURTHI, Under Secy.

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त 1970

एस०ओ० 2858.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 20 की उपधारा (3) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत्द्वारा निदेश देती है कि स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) में भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रेल 1970 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 1475 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा: नामतः—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 4 के सम्मुख की गई प्रविष्टि "डीन, मैडिकल कालिज, औरंगाबाद" के स्थान पर "निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, महाराष्ट्र बम्बई" की प्रविष्टि रख दी जायेगी।

[प०सं० 4-26/69-एम०पी०टी०]

आर० मूर्ति, अवर सचिव।

(Department of Works, Housing and Urban Development)

New Delhi, the 13th August 1970

S.O. 2859.—Whereas the Central Government has proposed to make modifications in the Master Plan for Delhi as regards the following areas:—

(1) Land at the junction of Lodhi Road and Kitchlew Marg;

(2) Land near Roshanara Garden;

the proposed modifications have been published as notice (No. S.O. 3073, dated the 15th October, 1966, at page 2901 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 15th October, 1966) as required by Sub-section (3) of section 11A of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), inviting objections and suggestions;

And whereas the Central Government has already approved the change in land use respect of item (1) *vide* notification No. 21017(29)/66-UD dated the 14th June, 1967;

And whereas the Central Government, at the time of issue of the aforesaid notification dated the 14th June, 1967, has not considered the objections and suggestions with regard to item (2) and had, until such consideration, deferred its decision with respect to that area;

And whereas the Central Government has now considered the objections and suggestions with regard to the area mentioned in item (2), that is to say, land near Roshanara Garden;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11A of the said Act in continuation of the aforesaid notification dated the 14th June, 1967, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, namely:—

Land situated near Roshanara Garden Subzimandi, Delhi which is according to the Master Plan for Delhi earmarked for 'retail business and recreational' may be changed to 'institutional' for locating a Government school.

[No. 21017(27)/66-UDI.]

L. M. SUKHWANI, Under Secy.

(निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग)

नई दिल्ली 13, अगस्त 1970

एस०ओ० 2859.—यतः केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिल्ली की वृहत योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है :—

(1) लोधी रोड और किचलू मार्ग चौराहे की भूमि;

(2) रोशनारा गार्डन के निकट भूमि;

प्रस्तावित संशोधनों को (भारत सरकार के दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के राजपत्र संख्या स० आ० 3073 के भाग–II खंड 3-उपखंड (II) के पृष्ठ संख्या 2901 पर) नोटिस के रूप में प्रकाशित करके, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जैसे कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11–ए की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने मद (1) के सम्बन्ध में दिनांक 14 जून, 1967 की अधिसूचना संख्या 21017(29)/66-यू०डी० के द्वारा भूमि के उपयोग में, परिवर्तन पहले ही अनुमोदित कर दिया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 14 जून, 1967 की उपर्युक्त अधिसूचना को जारी करते समय मद (2) के सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझावों पर विचार नहीं किया था तथा इस पर विचार होने तक उस क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय स्थगित कर दिया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने मद (2) में उल्लिखित क्षेत्र अर्थात् रोशनारा गार्डन के समीप की भूमि के सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझावों पर अब विचार कर लिया है ,

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14 जून, 1967 की पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली की उक्त वृहत योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश :—

रोशनारा गार्डन, सब्जी मण्डी, दिल्ली के निकट स्थित भूमि, जो दिल्ली की वृहत योजना के अनुसार "परचून व्यापार और मनोरंजन" के लिये उद्दिष्ट है, को सरकारी विद्यालय स्थापित करने के लिये 'सांस्थानिक' प्रयोग के लिये परिवर्तित किया जाए ।

[सं० 21017(27)/66-यू०डी० ।]

एल० एम० सुखवाणी,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Directorate)

New Delhi, the 14th August 1970

S.O. 2860.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst under the Posts and Telegraphs Directorate in the Department of Communications, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Posts and Telegraphs Directorate (Junior Analyst) Recruitment Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications**—(a) No person, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said post, and (b) no woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage, or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule

6 **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post

Recruitment Rules for the post of Junior Analyst in the Posts and Telegraphs Directorate

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or non Selection post	Age for direct recruit	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
Junior Analyst	One	General Central Service Class II Gazetted.	400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

Department of Communications.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment, by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	*Transfer on deputation*: Officersholding analogous posts under the Central Govt. or Grade IV Officers (Assistants) of the Central Secretariat service with 10 years service in the grade having experience and/or training in the application of work study or organisation and Methods Techniques. (Period of deputation Ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 2-9/68.Admn.]

संचार विभाग

(डाक तार निदेशालय)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1970

जी० एस० आर० 2860.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने संचार विभाग के डाक-तार निदेशालय में अवर विश्लेषक के पद के लिए भर्ती के तरीके का नियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाए हैं, यथा—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ** .—(1) ये नियम डाक-तार निदेशालय (अवर विश्लेषक) भर्ती नियमावली, 1970 कहलाएंगें ।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **लागू होना** .—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**.—पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में हुए उल्लेखानुसार होंगे ।

4. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य योग्यताएं** .—भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं और इस पद से संबंधित अन्य बातें उपयुक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किये गए उल्लेखानुसार होंगी ।

5. **योग्यताएं**.—(क) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए उसके जीवन काल में ही किसी अवस्था में दूसरा विवाह करता है जिसकी वजह से ऐसा विवाह प्रभावहीन हो जाता है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगा, और

(ख) कोई भी महिला जिसका विवाह उसके पति की एक अन्य पत्नी जीवित होने के कारण प्रभावहीन हो जाता है अथवा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी इस विवाह के समय पहले से एक पत्नी जीवित हो तो वह उक्त पदों पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगी ।

किन्तु केन्द्रीय सरकार यदि यह संतुष्ट करले कि ऐसा करने के कुछ विशेष आधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के बन्धन से मुक्त कर सकती है ।

6. **छूट देने का अधिकार।**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि किसी प्रकार की कार्रवाई आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रूप से संबंधित कारणों को देखकर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों, पदों के किसी भी वर्ग, श्रेणी के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबंधों को आदेश द्वारा शिथिल बना सकती है ।

अनुं

संचार विभाग के डाक तार निदेशालय में अवर-विश्लेषक

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सलेक्शन या गैर सलेक्शन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
अवर विश्लेषण	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II राजपत्रित	रु० 400–25–500–30–590–द० रो 30–800–35–900.	लागू न होने योग्य	लागू न होने योग्य	लागू न होने योग्य

सूची
के पद संबंधी भर्ती नियमावली

सीधी भर्ती के लिए क्या आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतिया की हालत में लागू होगी	परिवीक्षा काल यदि हो	भर्ती का तरीका या सीधी भर्ती से पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होने पर पदोन्नति द्वारा अन्य तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशत ।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की हालत में ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होना है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन किस प्रकार का है	वे परिस्थितिया जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
8	9	10	11	12	13
लागू न होने योग्य	लागू न होने योग्य	प्रतिनियुक्ति होने पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति होने पर स्थानातरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश्य पदों पर नियुक्त अधिकारी या ग्रेड III अधिकारी (सहायक) जो कि केन्द्रीय सचिवालय में कार्य कर रहे हैं और जिसकी उन ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा हो चुकी है तथा जिसका कार्य अध्ययन के लागू करने या संगठन तथा विधियों और तकनीकी संबंधी अनुभव/या प्रशिक्षण (साधारण तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो ।	लागू होने योग्य नही	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत आवश्यक है

[सं० 2-9/68 प्रशासन.]

(प्राणनाथ साही),
सहायक महानिदेशक (प्रशासन) ।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th August 1970

S.O. 2861.—The President hereby cancels the recruitment rules for the post of Junior Analyst under the Posts and Telegraphs Directorate in the Department of Communications as notified in S.O. 27 in Part II Section 3 (ii) of the Gazette of India dated the January 3, 1970.

[No. 2-9/68-Admn.]

P. N. SAHI,

Assistant Director General (Admn.).

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

(Indian Standards Institution)

New Delhi the 12 August, 1970

S.O.2862—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark (s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title (s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1 July 1970:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Rum	IS: 3811-1966 Specification for rum	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.
2		Whiskies	IS: 4449-1967 Specifition for whiskies	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.
3		Brandies	IS: 4450-1967 Specification for brandies	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proprtions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/ 13:9.]

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1970

ऐस० ओ० 2862—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम 1955 के नियम 4 के उपनियम (II) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से सूचना दी जाती है कि प्रमाणन चिन्ह जिसकी डिजाइन और शाब्दिक तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, भा मा संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित एक प्रमाणन चिन्ह 1 जुलाई, 1970 से लागू हो जाएगा ।

अधिसूची

क्रम संख्या	प्रमाणन चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	प्रमाणन चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS:381	रम	IS रम की विशिष्ट	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राफ जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी हुई है ।
2	IS:4449	हिविस्कियां	IS हिविस्कियां की विशिष्ट	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है

				और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी हुई है
3	IS:4450 ISI	ब्रैडियां	ब्रैडियो की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है।

[सं० सीएमडी 13:9]

S.O. 2863.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee (s) per unit for various Products details of which are given in the Schedule hereto annexed have been determined and the fee (s) shall come into force with effect from 1 July 1970:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rum . . .	IS: 3811-1966 Specification for rum	One litre	(*i*) 1 paisa per unit for the 1st 1,00,000 units and (*ii*) 0.5 Paisa per unit for the 100,001st unit and above.
2	Whiskies . .	IS: 4449-1967 Specification for whiskies	One litre	(*i*) 1 paisa per unit for the 1st 1,00,000 units, and (*ii*) 0·5 paise per unit for the 100,001st unit and above.
3	Brandies . .	IS: 4450-1967 Specification for brandies	One litre	(*i*) 1 paisa per unit for the 1st 1,00,000 units, and (*ii*) 0·5 paisa per unit for the 100,001st unit and above.

[No. CMD/13 : 10]

एस० ओ० 2863.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणनचिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसरणार्थ भारतीय मानक संस्था की ओर से सूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की मुहरांकन फीस, जिसके ब्योरे नीचे अनुसूची में दिए हैं, निर्धारित की गई है और यह फीस 1 जुलाई, 1970 से लागू हो जाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रम	IS : 3811–1966 रम की विशिष्टि	एक लीटर	(1) 1 पैसा प्रति इकाई पहली 1,00,000 इकाइयों के लिये (2) 100001वी इकाई और उससे ऊपर के लिए 0.5 पैसा प्रति इकाई
2.	ह्विस्कियां	IS : 4449–1967 ह्विस्कियों की विशिष्टि	एक लीटर	(1) 1 पैसा प्रति इकाई पहली 1,00,000 इकाइयों के लिए (2) 100001वीं इकाई और उससे ऊपर के लिए 0.5 पैसा प्रति इकाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	ब्रैंडियां	IS : 4450–1967 ब्रैंडियों की विशिष्टि	एक लीटर	(1) 1 पैसा प्रति इकाई पहली 1,00,000 इकाइयों के लिए (2) 100001वीं इकाई और उससे ऊपर के लिए 0.5 पैसा प्रति इकाई

[सं० सी एम डी/13 : 10]

New Delhi, the 13th August 1970

S.O 2864.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1st July 1970:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS:2226	Mouldboard plough, fixed type	IS: 2226-1962 Specification for mouldboard plough, fixed type.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2864.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम 1955 के नियम 4 के उपनियम (11) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से सूचना दी जाती है कि प्रमाणन चिह्न जिसकी डिजाइन और शाब्दिक तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिए हैं, या मानक संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह प्रमाणन चिह्न 1 जुलाई, 1970 से लागू हो जाएगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	प्रमाणन चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	प्रमाणन चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS:2226	मोल्डबोर्ड हल, जड़े प्रकार के	IS. :2226–1962 जड़े प्रकार के मोल्डबोर्ड हल की विशिष्टि ।	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है । और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है ।

[सं० सी एसडी/13:9]

S.O. 2865.—In pursuasce of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for mouldboard plough, fixed type details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1 July 1970

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. and Title of Relevant Indian/Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mouldboard plough, fixed type	IS: 2226-1962 Specification for mouldboard plough, fixed type	One piece	40 paise

[*No. CMD/13* : 10]

A. K. GUPTA,
Deputy Director General.

एस० ओ० 2865.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसरणार्थ भारतीय मानक संस्था की ओर से सूचित किया जाता है कि जड़े प्रकार के मोल्डबोर्ड हलों की मुहरांकन फीस, जिसके ब्यौर नीचे अनुसूची में दिए हैं, निर्धारित की गई है और यह फीस 1 जुलाई 1970 से लागू हो जाएगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद।उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक संस्था और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मोल्डबोर्ड हल जड़े प्रकार के	IS: 2226–1962 जड़े प्रकार के मोल्डबोर्ड हल	एक हल	40 पैसे

[संख्या सी एम डी 13:10]

ए० के० गुप्ता,
उपमहानिदेशक ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 20th August 1970

S.O. 2866.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th August, 1970.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL: DELHI.

PRESENT:

Shri R. K. Baweja, Central Government Industrial Tribnual Delhi.

New Delhi, the 27th July 1970

C. G. REFERENCE I.D. NO. 5 OF 1969

BETWEEN

The employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited.

AND

Their workmen.

Shri K. K Khullar—*for the Bank.*

Shri J. B. Kashyap—*for the workmen.*

AWARD

Vide Order No. 23/63/69-LRIII, dated 26th June, 1969, the Central Government referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited (hereinafter to be referred as the Bank) and their workman for adjudication to this Tribunal in respect of the matter specified in the schedule below:—

> "Whether the termination of the services of Shri Mohinder Kumar, waterman-*cum*-peon with effect from the 14th December, 1968 by the management of the National and Grindlays Bank Limited, 10, Parliament Street, New Delhi was legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. A statement of claim was filed on behalf of the concerned workman by the President of National and Grindlays Bank Staff Association (hereinafter to be referred as the Association) on the 5th of August, 1969 and a written statement was filed by the bank in reply thereto on the 23rd of September 1969. The Association also filed a rejoinder on behalf of the workman on the 9th of October, 1969. No issue arose out of the pleadings of the parties except what is covered by the term of reference given in the schedule above. Evidence, oral and documentary, was placed on record by the parties and in its light I now proceed to consider the above term of reference.

Term of Reference:

3. The facts in this case leading to the appointment, continuance in service and the termination of services of the workman are more or less admitted by the parties By an order dated the 20th of May, 1968 the concerned workman was appointed as a temporary water man-*cum*-peon at the Bara Hindu Rao Branch of the bank with effect from that date upto the 1st of June, 1968 *vide* Ext. W/1. Another letter dated the 31st of May, 1968 was issued to the workman extending his temporary appointment from 1st of June, 1968 to the 15th of June, 1968 *vide* Ext. W/2. His term of appointment was extended from time to time thereafter without any break and the last letter which the workman received is dated the 11th of December, 1968 *vide* Exts. W/3 to W/10. In the last letter the workman was informed that his period of service as a temporary waterman-*cum*-peon had been extended, but it would terminate finally on Saturday the 14th of December, 1968. It is also admitted by the parties as was stated by Shri Vishnu Bhagwan Uppal MW1 Accountant of the bank that the concerned workman was transferred from the Bara Hindu Rao Branch to the Parliament Street branch of the bank with effect from the 16th of August, 1968. On receipt of the letter dated 11th December, 1968 by which he was informed that his services would terminate finally on the 14th of December, 1968, the workman made a representation dated

14th of December, 1968 to the bank in which he stated that the three vacancies against which he and two others namely, Sarvashri Nagender Pershad and Shanti Swarup had been working were permanent vacancies, that the bank was not justified in terminating his services as he had put in more than three months of service and that under the Bipartite settlement he automatically stood confirmed *vide* Ext. W/11. The bank acknowledged the receipt of this letter sent by the workman *vide* its letter dated 19th December, 1968 Ext. W/12, and informed him that as there was no vacancy against which he could be absorbed, his request could not be acceded to. In his statement Shri Mohindar Kumar, the concerned workman deposed that the other two workmen who were his colleagues, though they had joined earlier as temporary hands, had been made permanent. He also admitted that he did not receive wages after the 14th of December, 1968. The case of the bank on the other hand as stated by Shri Vishnu Bhagwan Uppal Accounant was that as the workman had been appointed temporarily and the regional office at Delhi was not competent to create a vacancy, the order passed by the Bank on the 11th of December, 1968 was legal and justified. Reference was made to the permanent appointment of one Lalu another temporary peon-*cum*-waterman. The Accountant stated that when the services of Shri Lalu were terminated, a settlement was arrived at in the conciliation proceedings of which a copy is Ext. M/8. As a result of that settlement the bank stated, he was appointed as a permanent hand. It is not for me in these proceedings to give findings as to whether the permanent appointments of Shri Lalu or the other two workmen were justified or not because the full facts of those cases are not before me and they are not parties to the reference. The only point that falls for determination in these proceedings is, whether as a result of the continuous appointment on temporary basis of the concerned workman from the 20th of May to the 14th of December, 1968, could it be deemed that he stood automatically confirmed as a permanent peon-*cum*-waterman under the Bipartite settlement or the Bank Award?

4. The learned representative of the workman drew my attention to Para. 20.8 of the Bipartite settlement of which a reference was also made in Paragraph 3 of the statement of claim. It read as follows:—

> "A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such a temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy, the period of such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period."

The contention advanced on behalf of the workman was that under the above provision, as the workman had worked against a permanent sanctioned vacancy for more than three months, he automatically attained the status of a permanent employee and as such the bank was not justified in terminating his services. A mere persual of Para. 20.8 indicates that the bank has been empowered under this settlement to appoint a temporary workman in order to fill up a permanent vacancy but this period has not to exceed three months and during this period the bank has to make arrangement for filling up the vacancy permanently. It does not show by any strength of imagination that a temporary workman appointed against a permanent vacancy automatically becomes a permanent hand. I, therefore, see no merit in this contention that under the said provision of the settlement, the workman become a permanent hand.

5. The next argument addressed to me was that the workman though appointed temporarily for various periods from the 20th of May upto the 14th of December, 1968 was in fact, a probationer and when he had completed six months of the probationary period, he became a permanent employee under Para. 23.15 of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes) Award of 1962 known as the Desai Award. In para. 23.15 of the said award, the classification of workmen in the banking industry was made by the Tribunal, (a) "Permanent employee", (b) "probationer", (c) "temporary employee" and (d) "Part-time employee". Obviously, the concerned workman was not a permanent employee because he was not employee who was provisionally employed to fill a permanent vacancy or post employee who was provisionally employed to fill a permanent vacancy or post and had not been made permanent or confirmed in service. The copies of the various orders placed on the record show that the concerned workman was never employed to fill a permanent vacancy or post and so it cannot be said that the bank appointed him as a probationer. Apart from that, Shri Khullar, the learned representative of the bank contended that it was never alleged in the statement

of claim that the concerned workman was a probationer under the bank and he, therefore, pointed out that unless this arose out of the pleadings of the parties, the representative of the workman could not be permitted to press this point during the course of argument I think, this contention is correct because I find from the statement of claim that it was never alleged by the Association that he was appointed a probationer. What was stated was that as he was appointed against a permanent sanctioned vacancy for more than three months, he had become a permanent employee under the provision of para 20 8 of the Bipartite settlement Even if the learned representative of the workman is permitted to argue this point, as already shown above he noes not come within the ambit of the definition of "probationer" as given in the Desai Award

6. It was conceded by the learned representatives of the parties that the concerned workman was not a part-time employee. So, it is to be seen now if he fell within the purview of the definition of "temporary employee" as defined in the Desai Award Paragraph 21 20 and sub-clause (c) of Paragraph 23 15 of the Desai Award were superseded by para 20 7 of the Bipartite settlement in October, 1966. The definition of "temporary employee" as given in the Desai Award was amended by Para 20 7 of the Bipartite settlement in 1966 and it reads as follows —

> "Temporary Employee" will mean a workman who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature or who is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman."

The contention urged on behalf of the bank was that from May to August, 1968 the workman was employed as a waterman-*cum*-peon in the Bara Hindu Rao branch of the bank on account of the hot weather and that it was a temporary vacancy. This was so stated by Shri Vishnu Bhagwan Uppal MW1 Accountant of the bank He further added that after the hot weather, the workman was asked to work in the Parliament Street branch of the bank against a leave vacancy The bank also placed on the record on my direction, a statement indicating the leave availed of by members of the subordinate staff in the category of peons, waterman-*cum*-peons during the period from May, 1968 to December, 1968. It shows that the permanent subordinate staff in the category of peon-*cum*-waterman proceeded on leave during this period on various occasions and so, some posts of this category fell vacant due to their absence and the concerned workman alongwith others was permitted to work there So the statement of Shri Vishnu Bhagwan Uppal, that after his transfer from Bara Hindu Rao branch of the bank in August, 1968 the workman was appointed against leave vacancy caused by the absence of permanent incumbents, stands supported Now the definition of temporary employee as quoted above includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman The concerned workman was appointed in a temporary vacancy on account of the proceeding on leave of the permanent incumbents and so, in my view from August to December, 1968 he fell within this clause of the definition and was a temporary employee From May to August, 1968 he was appointed for a limited period for work which was of an essentially temporary nature *viz*., the supply of water during hot weather So the concerned workman was not a permanent hand, he was not a probationer, he was not a part-time employee and was obviously a temporary employee Under the terms and conditions, his services could be terminated and when [illegible] vacancy he was asked to quit with effect from the 14th of December, 1968 I, therefore, do not think that the bank in terminating his services violated the provisions of Paragraphs 20 7 and 20 8 of the Bipartite settlement or the Desai Award There is no allegation that the bank was actuated by any ulterior motive to terminate the services of the workman on account of his trade union activities But an attempt was made to show that the concerned workman was discriminated *vis-a-vis* other employees placed in the same position There were three permanent vacancies and it was stated in the statement [illegible] claim that against the two vacancies, Sarvashri Naginder Pershad and Shanti Swarup were absorbed Shri Mohinder Kumar in his statement admitted that they had joined earlier and so, they were senior to him If the bank employed those temporary hands as permanent ones then the concerned workman could have no grievance as they were admittedly senior to him The third permanent post was filled up by one Lalu to which the Association took exception It was alleged in the statement of claim that Shri Lalu had been working temporarily as a waterman-*cum*-peon that he left thereafter and that he was never in the continuous employment of the bank during the period from 20th May, 1968 upto the 14th of December, 1968 It was therefore, contended that he was not entitled to be absorbed

permanently against the third vacancy and that preference should have been given to the concerned workman. Copies of various letters issued by the bank to Shri Lalu have been placed on the record *vide* Exts. W/13 to W/26. They show that Shri Lalu was in the continuous employment of the bank from the 3rd of February 1967 upto the 12th of July, 1968. It seems that Shri Lalu filed a statement of claim before the conciliation officer for his reinstatement and on the 3rd of January 1969, a settlement was arrived at between the bank and the Association as a result of which the bank agreed to appoint Shri Lalu as a permanent hand with effect from the 21st of December, 1968 *vide* Ext.W/28. On the 4th of January, 1969, a letter was issued by the bank to Shri Lalu giving effect to the said settlement *vide* Ext. W/27. A copy of the service certificate Ext W/30 placed on the record reveals that Shri Lalu was born in 1937. It is to be noted that Shri Lalu was in the service of the bank for about 1½ years in a temporary capacity when his services were terminated on the 12th of July, 1968. The bank then on a reference to the conciliation officer in its wisdom settled the matter on the 3rd of January, 1969 and appointed him as a permanent hand against the third vacancy. There was nothing wrong in that and if the bank appointed as its permanent employee a person who was senior in service to the concerned workman then it cannot be said that the workman was discriminated. Had there been a fourth vacancy in December, 1968 or soon thereafter and if the bank had not considered the case of the workman for permanent absorption against that vacancy, then in that case it could be said that the workman was discriminated because the other three temporary employees had been taken as permanent hands and his claim was ignored. As the three persons who were employed happened to be senior in service to the concerned workman I do not think that the bank committed any error in absorbing them. The argument that Shri Lalu was more than 25 years of age and could not be appointed by the bank was not pressed nor was any provision of the Bank award or Bipartite settlement shown to me that the bank had not the discretion to do so. So, the allegation of discrimination against the concerned workman is not well-founded and ought to be ignored.

7. A number of authorities were cited on behalf of the bank and a few on behalf of the workman. I need not refer them because they are not very relevant and no legal point which requires the support of the authority was expounded before me. The case is more or less based on the provisions of the Bipartite settlement and the Desai Award which I have discussed above.

8. For the aforesaid reasons, I hald that the order terminating the services of the workman passed by the bank was legal and justified. Shri Mohinder Kumar, waterman-*cum*-peon is not entitled to any relief in these proceedings and the award is made accordingly.

(Nine pages)

(Sd.) R. K. BAWEJA,
Central Govt. Industrial Tribunal,
Delhi.

27*th July*, 1970

[No. F. 23/63/69-LRIII.]

S.O. 2867.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Sarvashri V. J. Pathak, B. G. Dalal, N. M. Shah, R. B. Parmar, K. M. Sanghavi and A. N. Mehta, employees of Advance Insurance Company Limited, which was received by the Central Government on the 14th August, 1970.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
BOMBAY

COMPLAINT NO. CGIT-15 OF 1969

ARISING OUT OF REF. CGIT-25 OF 1968

PARTIES:

1. Shri V. J. Pathak,
2. Shri B. G. Dalal,
3. Shri N. M. Shah,
4. Shri R. B. Parmar,
5. Shri K. M. Sanghavi,
6. Shri A. N. Mehta—*Complainants*

Versus

M/s The Advance Insurance Co. Ltd., Opp. Party.

PRESENT:

Shri A. T. Zambre, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the complainants—Shri J. G Gadkari, Advocate.
For the Opposite party—Shri P. Ramaswami, Advocate.

STATE: Maharashtra INDUSTRY: General Insurance.

Bombay, dated the 23rd July, 1970

AWARD

Six employees of the Advance Insurance Co. Ltd., have filed this complaint against the management for contravention of section 33 of the Industrial Disputes Act by terminating their services and have prayed for reinstatement.

2. It is alleged that the company resorted to the action of *mala fide* termination of the services of the employees under the garb of retrenchment alleged to have been caused due to reduction of work which excuse was false. They have contended that in fact the business of the company was being transferred to the sister concern M/s. Hukumchand Insurance Co. and the closure of the branches and reduction of work had not been due to factors beyond the control of the company but has been brought about with an ulterior motive of frustrating the pending reference and depriving the workmen of the benefits of the award. It has been further contended that in terminating the services, the company has not followed the rule of 'Last come first go with a view to discriminate against the employees who had been loyal to the union and the action of the company in retrenching the services of the complainants who were senior employees while retaining the junior employees in service was illegal and improper and the company had contravened the provisions of section 33 of the Industrial Disputes Act.

3. The management had by their written statement in reply denied the allegations and had contended that the company had to retrench the services of the workmen due to the closure of almost all the branches all over India resulting in a considerable reduction of the business and work and the retrenchment could not be called a matter for complaint under section 33A. It has been further contended that the petitioners had absolutely no relationship to the pending matter in the reference before this Tribunal and there was no question of victimization of the petitioners as alleged. They have denied that they had acted in a *mala fide* or vindictive manner and have contended that the retrenchment was affected *bona fide* and the employees are not entitled to any relief.

4. The complaint was hotly contested. Both the parties had filed various documents and tabular statements. They had also adduced oral evidence but at the time of arguments they settled the dispute and have filed consent terms requesting the Tribunal to pass an award.

5. As per the consent terms the union has agreed to withdraw all their statements submissions and contentions made by them against the company in the complaint and the company has agreed to pay to the six complainants Rs. 6000/- in full and final settlement of the claim in connection with their retrenchment. The record shows that the company has closed almost all its branches and had effected retrenchment due to deduction of business and considering the circumstances in my opinion the terms of settlement are fair and reasonable and I pass an award in terms of the consent terms annexure A which shall form part of this Award. Hence my award accordingly.

6. Submit this award to the Government under section 33A of the Industrial Disputes Act.

(Sd.) A. T. ZAMBRE,

Presiding Officer,

Central Government Industrial Tribunal,

Bombay

ANNEXURE 'A'

BEFORE SHRI A. T. ZAMBRE, HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Re: Complainant under section 33A of Industrial Disputes Act.

Shri V. J. Pathak and Others—*Complainants.*

Versus

M/s. Advance Insurance Co. Ltd.- *Opposite Party.*

Consent Terms

1. The Company agrees to pay and the Complainants agree to receive Rs. 6,000/- (Rupees Six Thousand Only) in full and final settlement of the claim in connection with the retrenchments of the employees made by the Co.

2. The Union agrees to withdraw all their statements submissions and contentions made by them against the Co., made in the Complaint.

3. The parties pray that An award may be passed accordingly.

Dated this 21st day of July 1970.

(Sd.) P. PAWASWAMI,
The Advocate for the Co.

(Sd.) J. G. GADKARI,
Advocate for Union.

[No. 40/31/70-LRI.]

ORDERS

New Delhi, the 13th August 1970

S.O. 2868.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Calcutta and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Calcutta-1, in terminating the services of Shri Laxmidhar Pandab, a sub-staff with effect from the 21st April, 1970 is justified? If not, to what relief is he entitled and from what date?

[No. 23/85/70-LRIII.]

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार, विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1970

का० आ० 2868.—यतः, केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हांककांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या हांककांग एण्ड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, कलकत्ता–1 के प्रबन्धतंत्र की श्री लक्ष्मीधर, पांडव, सब-स्टाफ की सेवाओं का 21 अप्रैल 1970 से पर्यवसान करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ?

[सं० 23/85/70-एल० आर० III.]

New Delhi, the 17th August 1970

S.O. 2869.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta, in terminating the services of Sarva Shri Ranjit Naik and Raghu Jamadar, with effect from the 7th January, 1970 is justified? If not, to what relief are they entitled and from which date?"

[No. 40/21/70-LR.I.]

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1970

का० आ० 2869.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हिन्दुस्तान जनरल इन्श्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या हिन्दुस्तान जनरल इन्श्योरेंस सोसाइटी, लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री रणजीत नाइक और रघु जमादार की सेवाओं का 7 जनवरी, 1970 से पर्यवसान करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं?

[सं० 40/21/70 एल० आर-I]

एस० एस० सहस्रनमन, अवर सचिव।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th August 1970

S.O. 2870:—In the notification of the Government of India, Ministry of Labour, Employmen and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. 2530, dated the 22nd July, 1970 published in Part II section 3 Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 22nd July, 1970, the following corrections be made:—

Page No.	*For*	*Read*
1117 6th line	entirely	entirety
1119 30th line	588	585
42nd line	exercise	exercised
1121 16th line	Rs. 50/- p.m.	to be deleted
1122 31st line In the table under "Name of diseases"	polismyelitis	poliomyelitis
1128 6th line	—	Between the words 'uniform' and 'under' add the word 'as'
1129 10th line	casua	casual
35th line	hercvy	hereby
1130 8th line	abve	above
47th line	upto	unto
1132 44th line	obserbed	observed
1133 54th line	unions	union
1137 7th line	disputes	dispute
Appendix"III	S.O. 4209	S.O. 4299
1138 18th line	P. M. NAYAR	P. M. NAYAK

[No. 25/24/68-LR-III (LR. I)]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 25th August 1970

S.O. 2871.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispuate between the employers in relation to the management of Messrs Daulatram Rameshwarlal Post Box No. 1942, Andhra Bank Building, Madras-I and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th August, 1970.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

Monday the 13th day of July, 1970

PRESENT:

Thiru S. Swamik Kannu, B.Sc., M.L. Industrial Tribunal, Madras.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 47 OF 1970

(In the matter of the dispute for adjudication u/s. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 between a worker and the managements of Shri J. K. Bhuwalka, Proprietor of

Agarwala Trading Co., and Messrs Daulatram Rameshwarlal Co., P. B. No. 1942, Andhra Bank Buildings, Madras-1).

BETWEEN

Sri Rambilas Sharma, 14A, Venkatachalam Chetti Street, Erode-1.

AND:

Sri J. K. Bhuwalka, proprietor of Agarwala Trading Company, P.B. No. 1942, Andhra Bank Buildings, Madras-1.

2. The Management of M/s. Daulatram Rameshwarlal Co., P.B. No. 1942, Andhra Bank Buildings, Madras-1.

REFERENCE:

Order No. 36(18)/69-LRIV dated 8th September, 1969 f the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference and all other material papers on record and the worker having sent a letter stating that the claim has been settled and withdrawn and recording the same this Tribunal made the following.

AWARD

This is an industrial dispute referred by the Central Government of India by its order dated 8th September, 1969, of a dispute between the employers of M/s. Daulatram Rameshwarlal, Post Box No. 1942, Andhra Bank Buildings, Madras-1 and Sri Rambilas Sharma, ex-employee, in respect of the termination of service of the said employee.

2. Summons was served on the management on 7th July, 1970. Parties are absent today. A copy of letter dated 20th March, 1970 by the claimant addressed to the management has been received wherein it is stated that the matter in issue had been settled and as such the matter may be treated as withdrawn. A letter from the management dated 7th July, 1970 has been received in this Tribunal stating that the claim was settled and the copy of the letter written by the claimant has also been sent to the Tribunal. It is also stated in this letter that no further action is necessary in the matter and the case may be closed. Under these circumstances, the claim is dismissed as withdrawn. An award is passed accordingly.

(Sd.) S. SWAMIKKANNU,
Industrial Tribunal.

List of witnesses examined:
For both sides: None.

List of documents Marked:
For both sides: Nil.

[No. 36(18)/69-LR-IV.]

P. C. MISRA, Under Secy.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970